

रूपा अशोक हुर्रा

वी.

अशोक हुर्रा और ए. एन. आर.

अप्रैल 10,2002

[ एस. पी. भरुचा, सीजे। , सैयद शाह मोहम्मद कादरी, उमेश सी. बनर्जी, एस. एन. वरियावा और शिवराज वी. पाटिल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 12 और 32-लेखन याचिका-प्रमाणपत्र लेखन-चुनौतीपूर्ण

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वैधता-----

----

12 .

अनुच्छेद 142-पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार-अंतर्निहित शक्तियों के तहत अनुमति-आयोजित, न्यायालय अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय की घोर गर्भपात को ठीक करने के लिए दुर्लभतम मामलों में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है-इस तरह के पुनर्विचार के लिए आधार और प्रक्रिया-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966-आदेश XL VII नियम 6।

सिद्धांत:

पूर्व ऋण न्याय का सिद्धांत-- की प्रयोज्यता

टकटकी निर्णय का सिद्धांत-चर्चा की गई।

तत्काल रिट याचिकाओं में विचार के लिए आम सवाल यह थे कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को उच्चतम न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाने के लिए बनाए रखा जा सकता है।

उक्त निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका खारिज कर दी गई थी; और क्या इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समीक्षा याचिका को इस आधार पर खारिज करने के बाद इसकी अंतर्निहित शक्तियों के तहत सही किया जा सकता है कि यह या तो अधिकार क्षेत्र के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में या पक्षपात के लिए गुंजाइश देने वाली अनुचित प्रक्रिया के कारण पारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ या किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय का गर्भपात हुआ।

इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए न्यायालय ने



रूपा अशोक हर्षा "अशोक हर्षा"

पकड़ना: प्रति कादरी, जे. (अपने लिए, सी. जे., वरियावा और पाटिल, जे. जे.)

1.1 . इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश पर हमला नहीं किया जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा एक याचिका चाहे वह मामले में एक पक्ष था या नहीं। [ 1019 - जी ]

1.2 . ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और रिट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

अधिकारिता, जो निम्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों पर एक पर्यवेक्षी अधिकारिता है, सिद्धांत रूप से न्यायालयों को समन्वित करने के लिए प्रमाणपत्र का एक रिट और उच्च न्यायालयों को एक फोर्टियोरी जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय को एक रिट जारी नहीं कर सकता है; और न ही एक उच्च न्यायालय की एक पीठ उसी उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ को एक रिट जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को प्रमाणपत्र की रिट जारी करने की मांग करने के लिए उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को बहुत कम लागू किया जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालयों के निर्णय/आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 132, 133 और 134 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में सुधार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, उच्च न्यायालयों का गठन संवैधानिक योजना में निचली अदालतों के रूप में नहीं किया गया है।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो एक छोटी पीठ और न ही सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ को रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 को केवल भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है और यह एक

कानून में तय स्थिति कि न्यायिक कार्यवाहियों में किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश को भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या अन्य प्राधिकरणों के दायरे में नहीं आते हैं।

[ 1015 - डी-जी ]

नरेश श्रीधर मिराईकर और अन्या. वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्ना , [ 1966 ]

3 एससीआर 744; ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्ना , [ 1988 ] 2 एस. सी. सी. 602; श्रीमती. त्रिवेणीबेन बनाम. गुजरात राज्य, [1989] 1 एस. सी. सी. 678; कृष्ण स्वामी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , [ 1992 ] 4 एस. सी. सी. 605; मो. असलम वी। भारत संघ, [1996] 2 एस. सी. सी. 749; खोदाव डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्ना वी. महापंजीयक, उच्चतम न्यायालय

भारत के, [1996] 3 एस. सी. सी. 114; गुरबचन सिंह और अन्ना , [ 1996 ] 3 एस. सी. सी. 117; बाबू सिंह और अन्ना वी. भारत संघ और अन्ना , [1996] 6 एस. सी. सी. 565; पी. अशोकन बनाम। भारत संघ और एएनआर। , [ 1998 ] 3 एस. सी. सी. 56; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

बनाम। भारत संघ और एएनआर। , [ 1998 ] 4 एस. सी. सी. 409 और एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा और अन्न राज्या , [ 2000 ] 1 एस. सी. सी. 278, संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण (पुनः प्रकाशन), खंड। I (1), संदर्भित

को।

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

1008

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 . यह न्यायालय, अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और एक सकल इलाज के लिए न्याय की विफलता, अपने अंतर्निहित निर्णयों का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकती है

शक्ति। [ 1023 - बी-सी]

2.2 . उच्चतम न्यायालय के संबंध में उसके बाध्यकारी होने से हटकर सिद्धांत पूर्ववर्ती उन आधारों से अलग हैं जिन पर दोनों के बीच अंतिम निर्णय होता है। पक्षों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हालांकि, जब एक पर पुनर्विचार किया जाता है इस न्यायालय के निर्णय से घोषित कानून से जुड़ी अंतिमता मांगी गई है।

और अंतिम उपाय और न्याय वितरण न्यायालय के निर्णय की अंतिमता इस आधार पर किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने पर कि वह दूषित है,

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन या आशंका की गुंजाइश देना।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले न्यायाधीश के कारण पक्षपात नहीं

मामले में किसी पक्ष के साथ अपने संबंधों का खुलासा करना, या मामले के दुरुपयोग के कारण

न्यायालय की प्रक्रिया। इस तरह का निर्णय, अंतिमता सुनिश्चित करने से दूर, हमेशा रहेगा।

अनिश्चितता के बादल के नीचे रहें। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, निश्चित रूप से मानव दोष की सीमा के अधीन, फिर भी

दुर्लभतम मामलों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनकी आवश्यकता होगी न्याय के सही गर्भपात को निर्धारित करने के लिए अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार

शिकायत की। ऐसे मामले में यह न केवल उचित होगा बल्कि अनिवार्य भी होगा। गलती को सुधारने के लिए कानूनी और नैतिक दोनों तरह से। इनमें न्याय करने का कर्तव्य

दुर्लभतम मामलों को निश्चितता की नीति पर हावी होना होगा

देश में अंतिम अदालत को चुनौती देने के लिए खुला नहीं होना चाहिए फिर भी वहाँ हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ हों, जिनमें निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार किया जाएगा

न्यायिक विवेक के लिए दमनकारी और अपरिवर्तनीय अन्याय को कायम रखने का कारण बनेगा। [ 1023 - ई; 1031-ई-एच; 1032-ए]

केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनामा आयकर आयुक्त-बॉम्बे नॉर्थ,

[ 1965 ] 2 एस. सी. आर. 908; मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनामा ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्या , [ 1974 ] 2 एस. सी. सी. 402; द इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड v. आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, [1972] 2 एस. सी. सी. 150; पुनः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, [1993] पूरका 1 एससीसी 96: 1991 पूरका 2 एस. सी. आर. 497; एस. नागराज और अन्या वी. कर्नाटक राज्य और अन्न , [ 1993 ] पूरका 4 एस. सी. सी. 595; रामदेव चौहान बनाम असम राज्य, [2001] 5 एस. सी. सी. 714; लिली थॉमस और अन्या वी. भारत संघ और ओआरएसा , [ 2000 ] 6 एस. सी. सी. 224; भारत संघ और अन्न आदि वी। एलआर द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)। आदि , [ 1989 ] 2 एस. सी. सी. 754; हरबंस सिंह बनामा उत्तर प्रदेश राज्य और अन्या , [ 1982 ] 2 एस. सी. सी. 101; ए. आर. अंतुले बनामा आर. एस. नायक

और एन. आर. , [ 1988 ] 2 एस. सी. सी. 602; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनामा भारत संघ 1009

रूपा अशोक हुरी बनामा। अशोक हुरी

और एन. आर. , [ 1998 ] 4 एस. सी. सी. 409; पुनः विनय चंद्र मिश्रा, [1995] 2 एस. सी. सी. 584

और एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा और अन्न राज्या , [ 2000 ] 1 एस. सी. सी. 278, संदर्भित।

लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड 'वी। लंदन देश

परिषद, एल. आर. 1898 अपील मामले 375; होयस्टेड और अन्या। वी. कराधान आयुक्त आई. आर. 1926 अधिनियम 155; राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी बनामा। राय बहादुर सुखराज राय और अन्या। आदि, ए. आई. आर. (1941) एफ. सी. 1,2: ( 1940 ) 2 एफ. सी. आर. 78: 1941 1 एमएलजे सपा 45 ; वेंकट नरसिम्हा अप्पा रो बनामा। कोर्ट ऑफ वाइर्स 1886 (II) अपील

मामले 660; लॉयड्स बैंक लिमिटेड बनामा। डॉसन और ओआरएस। , [ 1966 ] 3 सभी ई. आर. 77; जोन्स वी। सामाजिक सेवा आदि राज्य सचिव, (1972) 1 सभी ई. आर. 145; फिट्ज़लीट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम चेरी (कर निरीक्षक), (1977) 3 सभी ई. आर. 996; संयुक्त राज्य अमेरिका बनामा। ओहायो पावर कंपनी। लॉयर्स एंड 2nd 683 और आर. वी. बो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन वजीफा मजिस्ट्रेट और अन्या। पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्ते, (संख्या 2) (1999) 1 सभी ई. आर. 577, संदर्भित।

अहरोन बराक द्वारा 'न्यायिक विवेकाधिकार', संदर्भित।

2.3 . एक याचिकाकर्ता राहत पूर्व ऋण न्याय का हकदार है यदि वह स्थापित करता है

( 1 ) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन इस मायने में कि वह एल. आई. एस. का पक्षकार नहीं था, लेकिन निर्णय उसके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या, यदि वह एल. आई. एस. का पक्षकार था, तो उसे कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई और मामला इस तरह आगे बढ़ा जैसे कि उसे सूचना दी गई हो और (2) जहां कार्यवाही में कोई न्यायाधीश विषय-वस्तु के साथ अपने संबंध का खुलासा करने में विफल रहा हो या पक्षकार जो इस मामले के लिए गुंजाइश दे रहे हों।

पक्षपात की आशंका और निर्णय याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

[ 1035 - बी]

2.4 . याचिकाकर्ता, उपचारात्मक याचिका में, विशेष रूप से यह स्पष्ट करेगा कि

उसमें उल्लिखित आधारों को समीक्षा याचिका में लिया गया था और इसे प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपचारात्मक याचिका में शामिल होगा -

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन। [ 1035 - सी]

2.5 . चूंकि यह मामला इसके अंतिम निर्णय की पुनः जांच से संबंधित है।

न्यायालय, हालांकि सीमित आधार पर, उपचारात्मक याचिका को पहले तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों और उन न्यायाधीशों की पीठ को वितरित किया जाना चाहिए, जिन्होंने यदि उपलब्ध हो तो निर्णय पारित करने की शिकायत की थी। यह तभी होता है जब उक्त पीठ के अधिकांश न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है कि इसे उसी पीठ (जहां तक संभव हो) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो उचित आदेश पारित कर सकती है।

सुधारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी स्तर पर पीठ के लिए यह खुला रहेगा कि वह किसी वरिष्ठ वकील से न्यायमित्र के रूप में उसकी सहायता करने के लिए कहे। पीठ द्वारा किसी भी स्तर पर यह अभिनिर्धारित करने की स्थिति में कि याचिका बिना किसी गुण के और परेशान करने वाली है, वह 1010

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

याचिकाकर्ता पर अनुकरणीय लागत अधिरोपित करें। [ 1035 - डी-ई]

प्रति बनर्जी, जे। (सहमत)

1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक रिट क्षेत्राधिकार की परिकल्पना की गई है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उपलब्ध नहीं है इस न्यायालय से। [ 1037 - एच; 1038-ए]

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्या वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्ना , [ 1966 ]

3 एससीआर 744; ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्ना , [ 1988 ] 2 एस. सी. सी. 602; श्रीमती. त्रिवेणीबेन बनाम. गुजरात राज्य, [1989] 1 एस. सी. सी. 678 और अजीत कुमार बारात बनाम।

सचिव भारतीय चाय संघ और अन्या। , [ 2001 ] 5 एस. सी. सी. 42, पर भरोसा किया।

2.1 . पूर्व ऋण न्याय का सिद्धांत संबंधित है और इससे उत्पन्न होता है

कानून द्वारा न्यायालयों का उदय नहीं होगा। हालांकि इस न्यायालय का कोई आदेश नहीं हो सकता है न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में वर्णित, लेकिन तथ्य

न्याय के उद्देश्यों के लिए अंतर्निहित शक्ति की उपलब्धता किसी भी तरह से नहीं हो सकती है

मना कर दिया। भारत के संविधान ने सर्वोच्च को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी

न्याय के कारण के साथ कानून की सर्वोच्चता प्रदान करने वाला न्यायालय

यह सबसे ऊपर है। इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग भी मान्यता प्राप्त है।

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XL VII नियम 6 द्वारा। 1039-बी-सी-डी]

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्ना , [ 1988 ] 2 एस. सी. सी. 602; कृत्रिम और

केमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्या , [ 1990 ] 1 एस. सी. सी. 109; एस. नागराज

और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्न , [ 1963 ] सप. 4 एस. सी. सी. 595 और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनामा। भारत संघ और एएनआर। , [ 1998 ] 4 एससीसी 409, संदर्भित को।

मेसर्स कैथरीनहोल्म बनामा। नोरेक्रिपमेंट ट्रेडिंग लिमिटेड, (1972) 2 ऑल ई. आर. 538;

ओस्टाइम (कर निरीक्षक) v. ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल प्रोविडेंट सोसाइटी, (1959) 3 ऑल ईआर 245; 1960 एसी 459 और कॉमनवेल्थ ऑफ मैसाचुसेट्स एट अल वी। संयुक्त राज्य अमेरिका, (92 एल एड 968), संदर्भित।

2.2 . प्रकट अन्याय लाइलाज होने के बजाय प्रकृति में ठीक करने योग्य है और

यह न्यायालय अपनी पवित्रता खो देगा और इस प्रकार संस्थापक पिताओं की अपेक्षाओं पर विश्वास करेगा कि न्याय सबसे ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रियात्मक कानून/प्रक्रियात्मक न्याय न्याय की अवधारणा से आगे नहीं बढ़ सकता है और यदि कोई आदेश प्रकट अन्याय पैदा करने के लिए खड़ा होता है, तो क्या उसे चुप रहने दिया जाएगा ताकि पक्षकारों को हमेशा प्रभावित किया जा सके या न्याय की अवधारणा को 1011 को हल करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए न्यायालय को सक्रिय करना चाहिए।

रूपा अशोक हुरा बनाम। अशोक हुरा

समस्या के प्रति गलत दृष्टिकोण। यदि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के माध्यम से न्याय के ऐसे प्रशासन का कोई प्रभाव पड़ता है या कोई आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया जाता है या जनता के विश्वास को प्रभावित करता है, जैसा कि न्याय वितरण प्रणाली में अखंडता के सिद्धांत के संबंध में तकनीकी रूप से नहीं होना चाहिए-न्याय के पाठ्यक्रम को उसी तरह से तौलें क्योंकि यह पूर्व-ऋण न्याय के सिद्धांत का वास्तविक प्रभाव है। [ 1044 - एफ-जी; 1045-डी-ई]

जे. रंगा स्वामी बनाम सरकार. ए. पी. और अन्या , आकाशवाणी (1990) एससी 535,

प्रतिष्ठित।

आर. वी. ससेक्स के न्यायाधीश, पूर्व पी. मैकार्थी, (1924) 1 के. वी. 256 और आर. वी. धनुष

स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट और अन्या , पूर्व पक्ष पिनोचेत उगार्ते (संख्या 2), (1999) 1 सभी ई. आर. 577, संदर्भित।

2.3 . उपचारात्मक याचिकाओं को नियमित के बजाय दुर्लभ माना जाना चाहिए।

और न्यायालय की प्रशंसा उचित चौकसी पर होनी चाहिए

न्याय वितरण प्रणाली की तीन बुनियादी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या अधिकार क्षेत्र के बिना या विवादग्रस्त विषय के साथ किसी न्यायाधीश के जुड़ाव या निकटता के कारण जनता का विश्वास हिलने की भी संभावना है। यह समय है कि प्रक्रियात्मक न्याय प्रणाली को वैचारिक न्याय प्रणाली को रास्ता देना चाहिए और विधि न्यायालय के प्रयासों को इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए। [ 1045 - एच; 1046-ए]

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सी) सं. 509

1997 .

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 245/99,338,325-326,663,680/2000,374/2001 और

108 1999 से।

सोली जे सोराबजी, महान्यायवादी, शांति भूषण, पी. ए. मोहम्मद,

अनिल बी. दीवान, राजीव दत्ता, के. के. वेणुगोपाल, डी. ए. दवे, पराग पी. त्रिपाठी,

रंजीत कुमार, डॉ. राजीव धवन, पी. एस. मिश्रा, सुश्री कामिनी जैसवाल, सुश्री ऐश्वर्या राव, सुश्री बिपाखु बोरठाकुर, पी. विठ्ठल राव, सुश्री गुणवंत दारा, सुश्री सुधा गुप्ता, विकास सिंह, यूनुस मलिक, सुश्री पल्लवी

परमार, प्रशांत चौधरी, प्रशांत भूषण, संजीव के. कपूर, नरेंद्र वर्मा, विशाल गुप्ता, संजय पाठक, अनिल मित्तल, के. के., मोहन, ए. टी. पात्रा, एस. सुकुमारन, निपुण मल्होत्रा, डॉ. सोनिया हर्षा, दिव्यांग के. छाया, वरुण गोस्वामी, ए. पी. मेध, ध्रुव मेहता, के. सी. कौशिक, प्रतीक जालान, मनीष सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

1012 .

सिंघवी, आर. एन. पोद्दार, सी. राधाकृष्ण, सुश्री सुषमा सूरी, एस. एन. टेरडोल,

संजय आर. हेगड़े, सत्य मित्रा, जी. प्रकाश, के. बी. रोहतगी, सुश्री अपर्णा रोहतगी जैन, मनोज अग्रवाल, रणजी थॉमस, जावेद एम. राव, विनीत सिन्हा,

अशोक अग्रवाल, राजेंद्र पी. डी. सक्सेना, बी. एस. बंधिया, वी. बी. सहारिया, राकेश

के. खन्ना, रितेश सिंह, सूर्यकांत, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री रेखा

पांडे, डी. एस. माहरा, बिमल रॉय जाड, विनीत कुमार, वी. के. सिद्धार्थन, बी. के. खुराना, एस. मुरलीधर, एस. वल्लीनायगम, सुश्री नीरू वैद, उपस्थिति के लिए

पार्टियाँ। व्यक्ति में (एन. पी.), डब्ल्यू. पी. सं. 374/2001 में याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे. इन रिट याचिकाओं में हैं

इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के रूप में हमारे सामने आएँ

संविधान पीठ को इस प्रकार टिप्पणी करते हुए पहली उल्लिखित रिट याचिका:

" क्या इस न्यायालय का 10 मार्च, 1997 का निर्णय दीवानी मामले में दिया गया है 1997 की अपील No.1843 को अमान्य माना जा सकता है और क्या

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को बनाए रखा जा सकता है

याचिका के बाद इस न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया गया है

उक्त निर्णय की समीक्षा को खारिज कर दिया गया है, हमारी राय में,

जिन प्रश्नों पर इस संविधान पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है

अदालत "।

अन्य रिट याचिकाओं को उस मामले से जोड़ा गया था। इन मामलों में संवैधानिक कानून का निम्नलिखित प्रश्न

विचार के लिए महत्व उत्पन्न होता है: क्या कोई पीडित व्यक्ति हकदार है

इस न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश के खिलाफ किसी भी राहत के लिए, खारिज होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत या अन्यथा पुनर्विचार याचिका।

सवाल का जवाब देने के हमारे प्रयास में, हम ध्यान देने के साथ शुरुआत कर सकते हैं

कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा स्थापित किया गया है जो अपनी अधिकारिता और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है और संसद को इसे आगे की अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने में सक्षम बनाता है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 32 और 131), सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की अपीलीय अधिकारिता (अनुच्छेद 132,133 और 134), अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए विवेकाधीन अधिकारिता और अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने के लिए बहुत व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की हैं जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है, जो निर्धारित तरीके से भारत के पूरे क्षेत्र में प्रवर्तनीय होगा (अनुच्छेद 142), किसी भी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी मामले को वापस लेने या किसी भी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति जैसी शक्तियां (अनुच्छेद 139) और निर्णय की समीक्षा करने के लिए रूपा अशोक हुर्रा v.

अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1013

उसके द्वारा घोषित या आदेश (अनुच्छेद 137)। आगे की अधिकारिता और शक्तियों का हस्तांतरण संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जाना बाकी है (अनुच्छेद 138)। संसद उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 134 (2), 139 और 140) को और अधिक शक्तियां प्रदान करने में भी सक्षम है। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून

भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा और अनुच्छेद 144 निर्देश देता है कि भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। यह एक अभिलेख न्यायालय है और इसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां हैं (अनुच्छेद 129)।

चूँकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इन रिट याचिकाओं में लागू किया गया है, इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों का विज्ञापन करेंगे। यह संविधान के भाग III में शामिल है और यहाँ उद्धृत किया गया है:

" 32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। -

( 1 ) उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है -

आश्वासन दिया।

( 2 ) सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और प्रमाणपत्र, जो भी हो, की प्रकृति के रिट शामिल हैं।

द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त

यह भाग।

( 3 ) खंड (1) और (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर खंड (2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है।

( 4 ) इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को इसके अलावा निलंबित नहीं किया जाएगा

जैसा कि इस संविधान द्वारा अन्यथा प्रावधान किया गया है।

ऊपर उद्धृत लेख के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें चार खंड हैं। खंड (1) उचित तरीके से उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है।

भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही-मौलिक अधिकार। खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के रिट सहित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति निहित है।

भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए जो भी उपयुक्त हो,

अनिवार्य, निषेध, यथास्थिति और प्रमाण-पत्र। उपर्युक्त खंड (1) और (2) में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद खंड (3) द्वारा, [2002] 2 एस. सी. आर. द्वारा सशक्त करने के लिए सक्षम है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1014

किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए सभी या खंड (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से कोई भी। द.

खंड (4) में सन्निहित संवैधानिक अधिदेश यह है कि अनुच्छेद 32

संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने को छोड़कर निलंबित।

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करता है

के स्वरूप में रिट सहित उचित निर्देश, आदेश या रिट जारी करना

संक्षेप में, सामान्य रूप से रिट और रिट की विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए उपयोगी विशेष रूप से प्रमाणपत्र जिसके साथ हम यहाँ संबंधित हैं। अंग्रेजी कानून में

दो प्रकार के रिट होते हैं-(i) न्यायिक प्रक्रियात्मक रिट जैसे समन की रिट,

प्रस्ताव की रिट आदि जो निश्चित रूप से जारी की जाती हैं; ये रिट नहीं हैं भारत में प्रचलित और (ii) मूल रिट जिन्हें अक्सर उच्च विशेषाधिकार के रूप में कहा जाता है

रिट ऑफ़ क्वो वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडमस, सर्टिओरारी और निषेध आदि। ; भारतीय उच्च न्यायालयों में अक्सर उनका सहारा लिया जाता है और

सुप्रीम कोर्ट "। ऐतिहासिक रूप से, निषेध एक रिट थी जिसके तहत शाही अदालतें

सामान्य कानून ने अन्य न्यायालयों को इसके अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने से प्रतिबंधित कर दिया।

सामान्य विधि न्यायालयों का अनन्य अधिकार क्षेत्र; प्रमाणपत्र जारी किया गया था

राजा की पीठ में समीक्षा के लिए या निम्न न्यायालय के अभिलेख को लाने के लिए

उस अदालत में मुकदमे के लिए अभियोग हटा दें; मेंडमस को निम्न स्तर का निर्देश दिया गया था

राजा के दरबार में उपस्थित। हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के संबंध में स्थिति है इस प्रकार वर्णित है, "संसद के न्यायालय का, या संसद में राजा का, जैसा कि कभी-कभी व्यक्त किया जाता है, इस देश में एकमात्र अन्य सर्वोच्च न्यायाधिकारण है।" राजंदर नारायण राय बनाम। विजय गोविंद सिंह, (1836) 1 मू। पी. सी. 117 वे विवेकाधीन रिट हैं लेकिन इस तरह के रिट जारी करने के सिद्धांत अच्छी तरह से परिभाषित हैं। पूर्व-संवैधानिक युग में विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र था

भारत में केवल तीन चार्टर उच्च न्यायालय 2 हैं, लेकिन संविधान के लागू होने के साथ, सभी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं -

संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत उन रिटों को जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं। रिट अधिकारिता के संबंध में, भारत में उच्च न्यायालयों को वस्तुतः इंग्लैंड में राजा की पीठ के न्यायालयों के समान स्थिति में रखा गया है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अंग्रेजी कानून में विशेषाधिकार रिट से जुड़ी तकनीकीताओं की हमारी संवैधानिक योजना के तहत कोई भूमिका नहीं है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक रिट

1. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण (पुनः जारी), खंड। 1 ( 1 ) पैरा 103।
2. बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालय।

रूपा अशोक हुर्रा बनामा। अशोक हुर्रा सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1015

अभिलेखों के लिए बुलाने और उचित रूप से पारित होने के लिए उनकी जांच करने के लिए प्रमाणपत्र

आदेश, एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है जो परीक्षण के लिए अपने रिकॉर्ड को प्रमाणित करता है। प्रमाण-पत्र निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय के निर्णयों को समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लाने के लिए निहित है ताकि न्यायालय यह निर्धारित कर सके कि उन्हें रद्द किया जाना चाहिए या ऐसे निर्णयों को रद्द किया जाना चाहिए। निषेध का आदेश उच्च न्यायालय से जारी किया गया एक आदेश है जो एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देशित करता है जो उस अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या कानून के विपरीत कार्य करने से मना करता है। प्रमाणपत्र और निषेध दोनों का उपयोग निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों और जनता के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

अधिकारी "।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और रिट क्षेत्राधिकार की प्रकृति की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, जो निम्न न्यायालयों पर एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है /

न्यायाधिकरण, हमारे विचार में, सैद्धांतिक रूप से न्यायालयों को समन्वित करने के लिए प्रमाणपत्र का एक रिट और उच्च न्यायालयों के लिए एक फोर्टियोरी जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता है और न ही उच्च न्यायालय की एक पीठ उसी उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ को रिट जारी कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय को प्रमाण पत्र। यद्यपि उच्च न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 132, 133 और 134 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में सही किया जाना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालयों का गठन हमारे संविधान में निचली अदालतों के रूप में नहीं किया गया है।

योजना। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो एक छोटी पीठ और न ही सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की किसी अन्य पीठ को रिट जारी कर सकती है। ऊपर यह बताया गया है कि अनुच्छेद 32 को केवल भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है और यह कानून में एक तय स्थिति है कि न्यायिक कार्यवाही में किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश को भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय भी राज्य या अन्य के दायरे में नहीं आते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत प्राधिकरण।

नरेश श्रीधर मिराजकर और ओआरएस में। वी. महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. , [ 1966 ] 3 एस. सी. आर. 744, कुछ पत्रकारों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मूल पक्ष पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक मौखिक आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें खुली अदालत में दिए गए गवाह के बयान के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि यह अनुच्छेद का उल्लंघन है।

3 . हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण (पुनर्कथन) खंड। (1) पैरा 109।

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

1016

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19 ( 1 ) ( a) भारत के संविधान का। इसके नौ विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या विवादित आदेश ने मौलिक का उल्लंघन किया है।

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार और यदि ऐसा है तो क्या इसके तहत एक रिट है

संविधान का अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को जारी करेगा। बेंच थी सर्वसम्मति से इस बात पर कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश उत्तरदायी नहीं था

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में। आठ

विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि न्यायिक आदेश को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार, जे. का विचार था

कि संविधान उच्च न्यायालयों को हीन नहीं मानता है

अदालतें ताकि उनके निर्णय एक रिट द्वारा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी न हों

उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र और अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है उच्च न्यायालय को प्रमाणपत्र का एक रिट जारी करना। उसी प्रभाव के लिए विचार हैं

शाह और बचाव, जे. जे. द्वारा व्यक्त किया गया। हालाँकि, अपने असहमत निर्णय में

हिदायतुल्ला, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय का एक न्यायिक आदेश,

यदि त्रुटिपूर्ण है, तो अनुच्छेद 136 के तहत अपील में सुधार किया जा सकता है

संविधान, फिर भी, उन्होंने राय दी कि उच्च का विवादित आदेश न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और

संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय का गठन न केवल स्पष्ट था लेकिन तार्किक भी। उनके प्रस्ताव के अनुमानित परिणामों के संबंध में,

विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की:

" यह सुझाव दिया गया था कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय को रिट जारी कर सकते हैं

और अन्य उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश या पीठ को और उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायाधीश या पीठ को एक रिट जारी कर सकता है

उसी अदालत में। यह एक गलत धारणा है। शुरुआत में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकते क्योंकि रिट

नीचे जाता है और ऊपर नहीं। इसी तरह, एक उच्च न्यायालय एक रिट जारी नहीं कर सकता है

एक और उच्च न्यायालय। रिट एक पर रखी गई अदालत में नहीं जाती है अधिकारिता के मामले में समान आधार। जहाँ काउंटी अदालत

इसे जारी किया गया (देखें): द न्यू पार कंसोल्ट लिमिटेड [1898 (1) क्यू. बी. 669] . " ( जोर दिया गया)

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्न , [ 1988 ] 2 एससीसी 602, सवाल

इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इस बात पर बहस की गई कि क्या आदेश दिनांकित है

16 फरवरी, 1984, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा पारित, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अपीलार्थी के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेते हुए और उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हुए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया कि उन्हें मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को सौंपा जाए।

अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे] 1017

पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों को एक ऐसी अक्षमता के रूप में चिह्नित करें जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है और इसलिए संपार्श्विक हमले में घोषित किया जा सकता है। हालाँकि, पाँच विद्वान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कहा कि न्यायालय को पूर्व-ऋण न्यायसंगत कार्य करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की अपने अंतर्निहित आदेश की समीक्षा करने की शक्ति के सवाल पर 4. न्याय की आवश्यकता के अनुसार, अधिकार के रूप में।

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

1018

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुखर्जी, ओझा और नटराजन, जे. जे. यह विचार व्यक्त किया कि न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में भी ऐसा किया जा सकता है।

रंगनाथ मिश्रा, जे. ने एक असहमतिपूर्ण राय दी कि अपील कर सकते हैं

पुनर्विचार याचिका के रूप में नहीं माना जाएगा। वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि वे तब थे) एक  
असहमत राय दी कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान नहीं करती हैं या

अधिकारिता का एक स्रोत है और उनका उपयोग उस अधिकार क्षेत्र की सहायता के लिए किया जाना है जो पहले से ही अनुच्छेद के तहत निर्णय को सही करने के लिए निवेशित है।

137 उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश एक्स. एल. नियम 1 के साथ पढ़ें और उसके लिए

उद्देश्य यह है कि मामला यथासंभव उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष जाना चाहिए।

इस सवाल पर कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र का एक रिट

इस न्यायालय के मुखर्जी और नटराजन, जे. जे. के पहले के आदेश को सही करने के लिए संविधान जारी किया जा सकता था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 32 के तहत किया जा सकता है यदि इससे वंचित किया गया था

मौलिक अधिकार। रंगनाथ मिश्रा, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने राय दी कि प्रमाणपत्र की कोई रिट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की पीठें इस न्यायालय की बड़ी पीठों के अधीन नहीं हैं। ओझा, रे, वेंकटचलैया और रंगनाथन, जे. जे. द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया है। इस प्रकार, उस मामले में 5 के बहुमत से: 2 यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का एक आदेश अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाण पत्र जारी करके सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं था। संविधान से।

श्रीमती में। त्रिवेणीबेन बनाम. गुजरात राज्य, [1989] 1 एस. सी. सी. 678, के लिए बोल रहा है

स्वयं और संविधान पीठ के अन्य तीन विद्वान न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति ओझा ने इसी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा:

" यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालत के फैसले को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती है  
अनुच्छेद

14 या 21 के तहत और इसलिए न्यायालय का निर्णय

मृत्युदंड को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती है।

मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. आर. अंतुले बनाम। आर. एस नायक, एकमात्र अधिकार क्षेत्र जिसका उपयोग करने की मांग की जा सकती थी

अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक कैदी को चुनौती दी जा सकती है

अंतिम न्यायिक निर्णय के बाद की घटनाएं घोषित की जाती हैं और यह

इसकी वजह यह है कि लंबी या अत्यधिक देरी के आधार पर

दोषी कैदी इस अदालत से संपर्क कर सकता है और यही है

इस न्यायालय द्वारा लगातार आयोजित किया गया। लेकिन यह इसके लिए खुला नहीं होगा।

अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को पीछे हटना या

एक सक्षम अदालत द्वारा दिए गए अंतिम फैसले की जांच करें और

दोषी कैदी को सजा देना और यहां तक कि आर. यू. पी. ए. अशोक हुर्रा बनाम पर विचार करते हुए भी।

अशोक हुरी [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1019

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या बाद की परिस्थितियों के साथ अत्यधिक देरी को माना जा सकता है

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि दंडादेश का निष्पादन

मृत्यु न्यायसंगत और उचित नहीं होगी।

जगन्नाथ शेट्टी, जे. ने इस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं की।

हम इसी दृष्टिकोण से अन्य मामलों में निर्णयों की चर्चा के साथ इस निर्णय पर बोझ डालना अनुचित मानते हैं। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इस न्यायालय की विभिन्न पीठों ने निम्नलिखित मामलों में एक ही सिद्धांत को दोहराया [ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और अन्न, [ 1988 ] 2 एससीसी 602; कृष्णा

स्वामी वी. भारत संघ और ओआरएस, [ 1992 ] 4 एस. सी. सी. 605, मो. असलम वी। भारत संघ, [1996] 2 एस. सी. सी. 749; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. महापंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, [1996] 3 एस. सी. सी. 114; गुरबचन सिंह और अन्न वी. भारत संघ और एएनआर, [ 1996 ] 3 एस. सी. सी. 117; बाबू सिंह बैस और अन्या वी. भारत संघ और ओआरएस, [ 1996 ] 6 एस. सी. सी. 565 और पी. अशोकन बनाम भारत संघ और एएनआर, [ 1998 ] 3 एससीसी 56।

हालाँकि, यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एएनआर, [ 1998 ] 4 एस. सी. सी. 409 एक संविधान पीठ और एम. एस. अहलावत बनाम हरियाणा और अन्न राज्या, [ 2000 ] 1 एस. सी. सी. 278 ए. तीन-न्यायाधीश पीठ, और अन्य मामलों में विभिन्न पीठों ने इसके पहले के फैसलों/आदेशों को रद्द कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक आवेदन में अदालत। लेकिन उन मामलों में कोई भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में मुद्दे में शामिल नहीं हुआ। इसलिए, उन मामलों को इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र का एक रिट इस न्यायालय के पहले के अंतिम फैसले को चुनौती देने के लिए होगा।

उपरोक्त मामलों में निर्धारित अनुपात के विश्लेषण पर, हम अपने सुविचारित विचार की पुष्टि करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन में लागू नहीं किया जा सकता है, चाहे वह मामले में एक पक्ष था या नहीं।

पक्षकारों के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्षता में, हम अभिलिखित करते हैं कि इन मामलों की सुनवाई के समापन पर उन सभी ने स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय नियम 1966 के आदेश XL नियम 1 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा के उपाय को समाप्त करने के बाद इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, पक्षों के लिए सभी विद्वान वकील और विद्वान [2002] 2 एस. सी. आर.

1020

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महान्यायवादी जो इस न्यायालय के नोटिस पर न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए,

यह दलील देने के लिए एक असामान्य सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया कि थका देने के बाद भी

व्यक्ति को इस अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक अवसर प्रदान किया जा सकता है न्यायालय की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग या सकल मामलों में राहत पाने के लिए न्यायालय

न्याय की विफलता क्योंकि इस न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रभावित पक्ष

किसी अन्य मंच का सहारा नहीं ले सकते।

श्री शांति भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के आदेश की अंतिमता का सिद्धांत था

अनुमति दी जाए और उस मामले की फिर से जांच की जाए जहां आदेश पारित किए गए थे अधिकार क्षेत्र के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, उल्लंघन

किसी भी मौलिक अधिकार या जहां घोर अन्याय हुआ है। उन्होंने आमंत्रित किया।

सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XLVII, नियम 6 की ओर हमारा ध्यान और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता थी और इस मामले में आने वाले मामले

उपरोक्त श्रेणियों की अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत जांच की जानी चाहिए।

इस न्यायालय से। विद्वान वकील के अनुसार अनुच्छेद 129 नहीं होगा इस न्यायालय के निर्णय को सही करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कोई अपील नहीं होगी, इसलिए इस न्यायालय के निर्णय को सही करने के लिए उपरोक्त आधारों में से किसी भी आधार पर एक आवेदन, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, जिसे अनुज्ञेय आधार के अस्तित्व के संबंध में एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतुले का हवाला दिया

मामला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मामला और अहलावत का मामला उदाहरण के रूप में जिसमें इस अदालत ने अपने पहले के फैसलों को सही किया था। उन्होंने वकालत की: ( i) इसके लिए

ऐसे आवेदन पर मौखिक सुनवाई और (ii) न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए

उन लोगों के अलावा जिन्होंने इस आधार पर आदेश पारित किया कि यह वादी जनता में विश्वास पैदा करेगा।

श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील, को गोद लेते हुए

श्री शांति भूषण के तर्कों ने प्रस्तुत किया कि आदेश XLVII, सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के नियम 6 के प्रावधान, केवल संविधान के अनुच्छेद 137 के प्रावधानों का पुनर्कथन है और इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को हुए अन्याय को दूर करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस न्यायालय के अंतिम आदेशों में सुधार की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों और चुनौती के तहत आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के उपाय से बाढ़ के द्वार नहीं खोले जाते हैं, इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने के लिए एक आवेदन के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि इसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और तुच्छ आवेदन के मामले में याचिकाकर्ता को लागत के अधीन किया जा सकता है। उन्होंने आर. यू. पी. ए. अशोक हुर्रा बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर भरोसा किया।

अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1021

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। ओहायो पावर कंपनी, [1 लॉयर्स एड। 2 डी 683] यह दिखाने के लिए कि प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में अदालतों ने अपनी गलतियों को ठीक किया है। उन्होंने हरबंस सिंह बनाम में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्या, [ 1982 ] 2 एस. सी. सी. 101 यह दिखाने के लिए कि समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया; उन्होंने इस तरह के आवेदन पर विचार करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने का अनुरोध किया।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनिल ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 129 ने इस न्यायालय को रिकॉर्ड की अदालत घोषित किया है, इसलिए इसके पास किसी भी पक्ष के साथ अन्याय को पूर्ववत करने के लिए उचित आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्तियां होंगी।

इस न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप। उन्होंने यह दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया कि इस अदालत द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया गया था और एक व्यथित व्यक्ति के पक्षकारों के साथ न्याय करने के लिए इस अदालत के पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया।

विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया उपाय इस न्यायालय के अंतिम आदेश से व्यथित व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा; फिर भी उन्होंने अन्य विद्वान वकीलों द्वारा आग्रह किए गए तर्कों का समर्थन किया कि न्याय की घोर विफलता के मामले में, इस न्यायालय को इस न्यायालय के अंतिम आदेश की जांच करने के लिए एक आवेदन पर विचार करके अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, भले ही एक समीक्षा खारिज कर दी गई हो, दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम। उनके अनुसार जहां आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था, मामला दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम में आएगा। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय के आदेश को भाग III के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

संविधान और इसलिए, उस आधार पर कोई राहत का दावा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एक्सएल नियम 1 के साथ पढ़ा जाता है। न्यायालय नियम, 1966 में इस न्यायालय के एक आदेश की समीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिस पर उसी पीठ द्वारा विचार किया जाएगा, जब तक कि वही न्यायाधीश पद छोड़ने के कारण उपलब्ध न हों। न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के तहत निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में उन्होंने राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी आदि मामले में संघीय न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। राय बहादुर सुखराज राय और अन्या। आदि, (1940) 2 एफ. सी. आर. 78]। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में सुधार के लिए या

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, एक उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है, जिसकी सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ-साथ आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों से बनी एक उपयुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।

विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने तर्क दिया कि चूंकि



" [ 2002 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1022

उच्चतम न्यायालय संविधान का सृजन है इसलिए सुधारात्मक शक्ति है

सर्वोच्च को अधिकारिता प्रदान करने वाले प्रावधानों से प्राप्त किया जाना

अनुच्छेद 32 और 129-140 जैसे न्यायालय; ऐसी शक्ति एक से उत्पन्न नहीं होती है

अमूर्त अंतर्निहित क्षेत्राधिकार। सुधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि - अधिकारिता की कमी के मामले में संकीर्ण अर्थों में अन्याय को ठीक करें,

एनिस्मिनिक के व्यापक अर्थों में नहीं, और प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन।

आर वी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर भरोसा करते हुए। बो स्ट्रीट मेट्रोपोलिटन

वजीफा मजिस्ट्रेट और अन्य।, पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्ते (नंबर 2) का मामला [ 1999 ]  
1 समस्त ई. आर. 577 उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति है -

अपने स्वयं के निर्णय को सही करें जहां एक पक्ष को बिना किसी गलती के किया गया है

पक्षपात के लिए गुंजाइश देने वाली अनुचित प्रक्रिया के अधीन। उनका आगे का तर्क

यह है कि सुधारात्मक शक्ति समीक्षा शक्ति और अनुच्छेद 129 की एक प्रजाति है,

137, आदेश XL नियम 5 और आदेश XLVII नियम 1 और 6 इंगित करते हैं कि यह न्यायालय

अपने स्वयं के निर्णय को सही करने की अंतर्निहित शक्ति है। उन्होंने निर्णयों का उल्लेख किया अंतुले के मामले में इस न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मामला,

अहलावत का मामला और त्रिवेणीबेन का मामला (ऊपर) हमें यह समझाने के लिए कि

न्यायालय पहले भी इस शक्ति का प्रयोग कर चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने

उस ओर से अभ्यास निर्देश भी जारी कर सकते हैं।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

इस न्यायालय की विभिन्न प्रकार की अधिकारिताओं से संबंधित संविधान के विभिन्न प्रावधानों और इस बात की वकालत की कि स्पष्ट अवैधता और स्पष्ट अन्याय के मामले में यह न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीठ की संरचना में वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों के साथ-साथ आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं, यदि उपलब्ध हो। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकट अवैधता और स्पष्ट अन्याय के आधार पर ऐसी उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार करते समय, दुर्लभतम मामलों में, इस न्यायालय द्वारा घोषित

कानून की अंतिमता और निश्चितता जैसे कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने द केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम में सात विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। आय आयुक्त-कर बॉम्बे उत्तर, [1965] 2 एस. सी. आर. 908, जिसके बाद मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किए गए सात विद्वान न्यायाधीशों की एक और पीठ आई। ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य।, [ 1974 ] 2 एस. सी. सी. 402 और द इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के मामले में पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। द.

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, [1972] 2 एस. सी. सी. 150। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले के निर्णय पर फिर से विचार करने की शक्ति बहुत सीमित होनी चाहिए; जब समीक्षा की शक्ति बहुत सीमित और सीमित है जैसा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, [1993] में संविधान पीठ के निर्णय से स्पष्ट है। 1 एस. सी. सी. 96 और तीन विद्वानों की पीठ आर. यू. पी. ए. अशोक हुर्दा बनाम।

अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.) 1023

एस. नागराज और अन्य में न्यायाधीश। वी. कर्नाटक राज्य और अन्ना, [ 1993 ] पूरका 4 एस. सी. सी. 595 और रामदेव चौहान बनाम। असम राज्य, [2001] 5 एस. सी. सी. 714 तीन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा और लिली थॉमस और अन्य के मामले में। वी. संघ का भारत और ओआरएस, [ 2000 ] 6 एस. सी. सी. 224 समीक्षा को खारिज करने के बाद प्रकट अवैधता और स्पष्ट अन्याय को सुधारने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग

याचिका को समीक्षा की शक्ति की तुलना में बहुत संकीर्ण होना चाहिए।

ये दलीलें सवाल उठाती हैं कि क्या इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समीक्षा याचिका को खारिज करने के बाद इसकी अंतर्निहित शक्तियों के तहत इस आधार पर सही किया जा सकता है कि यह या तो अधिकार क्षेत्र के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में या पक्षपात के लिए गुंजाइश देने वाली अनुचित प्रक्रिया के कारण पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ या किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला।

इस बात का कोई खंडन नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम उपाय का न्यायालय है-संवैधानिक सहित तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अंतिम न्यायालय।

कानून। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून है; यह अपने लिए और भारत में सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के लिए पूर्ववर्ती है। एक निर्णय में कानून की घोषणा होगी और पक्षकारों के बीच विवाद पर निर्णय देने के लिए मामले के तथ्यों पर इसका अनुप्रयोग होगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में उसके बाध्यकारी उदाहरण से हटकर सिद्धांत उन आधारों से अलग हैं जिन पर पक्षों के बीच अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यहाँ, हम मुख्य रूप से उत्तरार्द्ध से संबंधित हैं। हालाँकि, जब इस न्यायालय के किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जाती है, तो घोषित कानून के साथ-साथ मामले में किए गए निर्णय दोनों से जुड़ी अंतिमता को आम तौर पर चुनौती के तहत लाया जाता है। इसलिए, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उच्चतम न्यायालय की मिसाल के साथ इतना अधिक मूल्य जुड़ा हुआ था कि द लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी, लिमिटेड बनाम। लंदन काउंटी काउंसिल [एल. आर. 1898 अपील मामले 375], हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित किया कि कानून के प्रश्न पर उसका निर्णय निर्णायक था और बाद के मामलों में सदन को बाध्य करेगा और एक गलत निर्णय केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा सही किया जा सकता है।

होयस्टेड और ओआरएस में। वी. 165 पर कराधान आयुक्त, एलआर 1926 एसी 155, लॉर्ड शॉ ने कहा: पक्षकारों को नए मुकदमे शुरू करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे मामले के कानून के बारे में नए विचारों को स्वीकार कर सकते हैं, या नए संस्करण जो वे प्रस्तुत करते हैं कि अदालत द्वारा कानूनी परिणाम की उचित आशंका क्या होनी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होता, सिवाय तब जब कानूनी सरलता हो।

थक गया है। "2 एस. सी. आर.

1024

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसी प्रभाव के लिए भारतीय संघीय न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार है  
राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी के मामले में (ऊपर)  
वेंकट नरसिम्हा अप्पा पंक्ति बनाम में प्रिवी काउंसिल का आदेश। का न्यायालय  
वार्ड, [1886] (II) 664 पर अपील मामले 660]। ग्वायर, सीजे। के लिए बोलते हैं  
संघीय न्यायालय ने टिप्पणी की।

न ही यह केवल इस आधार पर समीक्षा करने के लिए आवेदनों को स्वीकार करेगा कि  
मामले में पक्षों की खुद को दुखी होने की धारणा है

निर्णय लें। हमारी राय में यह असहनीय और सबसे पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

जनहित के लिए यदि न्यायालय द्वारा एक बार निर्णय लिए गए मामलों को फिर से किया जा  
सकता है

खोला और फिर से सुना: " एक हितकारी उक्ति है जो होनी चाहिए  
अंतिम उपाय के सभी न्यायालयों द्वारा देखा गया अंत तक ब्याज का पुनः प्रकाशन

लीटियम। इसका सख्ती से पालन करने पर कभी-कभी कठिनाई हो सकती है।

व्यक्तिगत वादी, लेकिन उस स्रोत से उत्पन्न होने वाली शरारत होनी चाहिए

महान शरारत की तुलना में छोटा जो आवश्यक रूप से होगा

निर्णयों की अंतिमता पर संदेह किए जाने के परिणामस्वरूप  
इस तरह का एक न्यायाधिकरण "।

एस. नागराज के मामले (ऊपर) में, राज्य द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था  
पूर्व में पारित आदेश का स्पष्टीकरण। याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि कोई भी  
इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन या उसे वापस लेने का परिणाम होगा -

संविधान के अनुच्छेद 141 में निहित अंतिमता के सिद्धांत को नष्ट करना। सहाय, जे. ने  
अपने लिए और पांडियन के लिए बोलते हुए कहा:

" न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं को पार करता है। न ही नियम

प्रक्रिया और न ही कानून की तकनीकीताएँ इसके रास्ते में आ सकती हैं। का आदेश

न्यायालय को किसी के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होना चाहिए। टकटकी निर्णय का नियम है निरंतरता के लिए पालन किया जाता है लेकिन यह प्रशासनिक में उतना लचीला नहीं है सार्वजनिक कानून की तरह कानून। यहां तक कि कानून भी न्याय के सामने झुकता है।

राजा पृथ्वी चंद लाल के फैसले का जिक्र करते हुए विद्वान न्यायाधीश

चौधरी के मामले (ऊपर) ने आगे कहा: यहां तक कि जब कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए थे जिन परिस्थितियों में वह अपने आदेश को सुधार सकता था, अदालतों ने प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता से बचने के लिए ऐसी शक्तियों को हटा दिया।

पूर्ववर्ती की निर्णायक प्रकृति के संबंध में स्थिति

इंग्लैंड में लॉर्ड गार्डिनर द्वारा निम्नलिखित अभ्यास कथन दिए जाने तक,

5. यह राज्य को चिंतित करता है कि मुकदमों का अंत हो। यह राज्य के हित में है कि

यह कानूनी मुकदमे का अंत होना चाहिए।

अशोक हुरी "। अशोक हुरी [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1025

लॉयड्स बैंक लिमिटेड बनाम डॉसन और ओआरएस, [ नोट (1966) 3 सभी ई. आर. 77 पर

स्वयं और साधारण में अपील के स्वामी,

" इसलिए वे अपनी वर्तमान प्रथा को संशोधित करने का प्रस्ताव करते हैं और इस सदन के पूर्व निर्णयों को सामान्य रूप से बाध्यकारी मानते हुए, जब ऐसा करना सही लगता है तो पिछले निर्णय से हट जाते हैं।

उन्होंने कहा कि सदन द्वारा पहले के दृष्टिकोण से हटने के संबंध में सिद्धांत, अभ्यास कथन, लॉर्ड रीड के भाषण में V में परिलक्षित होता है। सामाजिक सेवाओं के राज्य सचिव, हडसन बनाम। राज्य सचिव सेवाएँ, (संयुक्त अपील) (1972) 1 सभी ई. आर. 145, जिन्होंने कहा:

" पुराना दृष्टिकोण यह था कि पूर्ववर्ती के कठोर पालन से कोई भी विचलन उस निश्चितता को कमजोर कर देगा। मैंने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और न ही करता हूँ। यह कुख्यात है कि जहाँ एक मौजूदा निर्णय अस्वीकृत है लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है, अदालतें अपर्याप्त आधारों पर इसे अलग करती हैं। मैं करता हूँ।

यह न सोचें कि वे ऐसा करने में गलत काम करते हैं; वे अपने लिए खुले एकमात्र विकल्पों में से कम बुरे को अपना रहे हैं। लेकिन इससे अनिश्चितता पैदा होगी क्योंकि कोई भी पहले से यह नहीं कह सकता कि किसी विशेष मामले में अदालत पुराने असंतोषजनक फैसले का पालन करने के लिए बाध्य महसूस करेगी या नहीं। संतुलन पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के निर्णय को रद्द करना

कानून की निश्चितता को बढ़ावा देगा और बाधित नहीं करेगा। लेकिन यह निश्चितता तब तक बाधित होगी जब तक कि इस अभ्यास का संयम से उपयोग नहीं किया जाता है। मैं उन मामलों को वर्गीकृत करने की कोशिश नहीं करूंगा जिनमें इसका उपयोग किया जाना चाहिए या जिन मामलों में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा अनुभव कुछ मार्गदर्शन प्रदान करेगा। लेकिन मैं यह राय रखूंगा कि एक पुराने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए विशिष्ट मामला वह है जहाँ कुछ व्यापक मुद्दा शामिल है, और यह केवल दुर्लभ मामलों में होना चाहिए कि हमें पुनर्विचार करना चाहिए।

कानून या अन्य दस्तावेजों के निर्माण के प्रश्न।

एन फिट्ज़लीट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम चेरी (कर निरीक्षक), [1977] 3 ऑल ई. आर. लॉर्ड विल्बरफोर्स ने कहा:

" मेरे स्वामी, मेरी दृढ़ राय में, 1966 के अभ्यास वक्तव्य का उद्देश्य कभी भी इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देना नहीं था और इसे अनुमति देने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। वास्तव में, अनुमति देने से अधिक अवांछनीय कुछ नहीं हो सकता है।

वादियों, इस सदन द्वारा सभी के साथ निर्णय दिए जाने के बाद

अंतिमता की उपस्थिति, इस आशा में इस सदन में लौटने के लिए कि

अलग तरह से गठित समिति को उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है जिसे उसके पूर्ववर्तियों ने अस्वीकार कर दिया था। यह सच है कि पहले का निर्णय था

बहुमत: मैं इसकी शुद्धता या 1026 की वैधता के बारे में कुछ नहीं कहता।

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तर्क जिसके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। कि दो प्रमुख थे

संभावित दृश्य प्रत्येक के लिए समर्थन द्वारा किसी भी दर पर दो से दिखाया जाता है।  
सदन के सदस्य। लेकिन संदिग्ध मुद्दों को हल करना होगा और

कानून उन्हें हल करने का कोई बेहतर तरीका नहीं जानता है

अंतिम न्यायाधिकरण की बहुमत की राय। इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है।

से प्रस्थान को उचित ठहराने के लिए इस तरह की राय की शुद्धता के बारे में संदेह

यह "।

लॉर्ड एडमंड-डेविस ने कहा:

" मेरे स्वामी, मैं सम्मानपूर्वक आपके विचारों को साझा करता हूँ कि चांसरी लेन

निर्णय [1966]। 1 सभ्य। ई. आर. 1 सही था। लेकिन मैं भी आया था

विपरीत निष्कर्ष, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं  
इसे अभी छोड़ना 'सही' नहीं सोचना चाहिए था। ऐसा करने के लिए

इसी तरह की अपीलों के लिए बाढ़ के द्वार खोलने के लिए होता और इस तरह

अनिवार्य आधार जिस पर यह तय किया जाए कि कानून क्या है और इसका  
अलग-अलग मामलों में आवेदन '।

अन्य देशों में मौजूद कानून का सारांश अहरोन ने दिया है।

बराक ने अपने ग्रंथ में कहा है:

राज्य अब अपने पूर्वजों से बंधा नहीं है। सर्वोच्च  
संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यायालय कभी भी अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं था, और

न ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल के हैं।

टकटकी निर्णय का सिद्धांत इस न्यायालय को किस हद तक बांधता है,

इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ क्या थी  
निर्णय के सिद्धांत को सेवा में दबाया जा सकता है

जहाँ तक टकटकी

अपने पहले के फैसलों को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग किया गया था। अदालत ने

उन्होंने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:

" जब यह न्यायालय कानून के प्रश्नों का निर्णय करता है, तो इसके निर्णय निम्नानुसार होते हैं -

अनुच्छेद 141, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, और इसलिए, इस न्यायालय का यह निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए कि कानून की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश किया जाए और बनाए रखा जाए।

6. " पृष्ठ 234 पर न्यायिक विवेकाधिकार।

रूपा अशोक हुर्रा बनाम। अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1027

देश। इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग करना कि बाद में न्यायालय के समक्ष रखा गया दृष्टिकोण अधिक उचित प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे लगातार बचा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के किसी अवसर पर, न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह पहले

निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, उसे त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए; लेकिन इससे पहले कि कोई पिछला निर्णय स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए कि

उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे।

मगनलाल छगनलाल के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न पर विचार किया: क्या कोई निर्णय

उत्तर भारत कैटर्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को खारिज करने की आवश्यकता थी। खन्ना, जे. ने कहा:

" साथ ही, यह ध्यान में रखना होगा कि निश्चितता और निरंतरता कानून के शासन के आवश्यक तत्व हैं। यदि देश का सर्वोच्च न्यायालय पहले के मामलों में उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार को आसानी से खारिज कर देता है, तो कानून में निश्चितता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और उसे गंभीर झटका लगेगा, भले ही वह विचार कई वर्षों से इस क्षेत्र में रहा हो। इस न्यायालय के समक्ष आने वाले कई मामलों में, दो विचार संभव हैं, और केवल इसलिए कि न्यायालय का मानना है कि पहले के मामले में न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया दृष्टिकोण मामले के बारे में बेहतर दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण के अतिनिर्णय को उचित नहीं ठहराएगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, और पूरे देश में कई मामलों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। बहुत से लोग अपने मामलों की व्यवस्था करते हैं और बड़ी संख्या में लेन-देन भी इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के विश्वास पर होते हैं। यह अनिश्चितता, अस्थिरता और भ्रम पैदा करेगा यदि इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कानून जिसके आधार पर कई मामलों का निर्णय लिया गया है और कई लेनदेन किए गए हैं।

स्थान को सही कानून नहीं माना जाता है।

द इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, प्रश्न

पाँच विद्वान न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष यह था: यह न्यायालय कब पिछले दृष्टिकोण से उचित रूप से असहमत हो सकता है?

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1028

इस न्यायालय के पूर्व आदेश के प्रभाव के संबंध में सावंत, जे।

कावेरी जल विवाद में संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए  
(ऊपर) इस प्रकार है:

न्यायाधिकरण का मामला

" कानून के सवाल पर इस न्यायालय का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी है।  
अदालतें और अधिकारी। अतः उक्त खंड के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं  
कानून के प्रश्न को केवल तभी संदर्भित करें जब इस न्यायालय ने इसका निर्णय नहीं लिया हो।  
दूसरा, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा केवल निम्नानुसार की जा सकती है -  
उच्चतम न्यायालय के आदेश XL के नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137  
नियम, 1966 और उसमें उल्लिखित शर्तों पर। कब, आगे,

यह न्यायालय पहले के एक मामले में अपने द्वारा व्यक्त किए गए कानून के दृष्टिकोण को  
खारिज कर देता है,

यह अपील में बैठकर और अपील का प्रयोग करते हुए ऐसा नहीं करता है।  
पहले के निर्णय पर अधिकार क्षेत्र। यह अपने अभ्यास में ऐसा करता है  
अंतर्निहित शक्ति और केवल असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि जब  
पहले का निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार होता है या इसके अभाव में दिया जाता है  
प्रासंगिक या भौतिक तथ्य या यदि यह स्पष्ट रूप से गलत और उत्पादक है  
सार्वजनिक शरारत। बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम देखें। की स्थिति  
बिहार, [1955] 2 एससीआर 603।

रामदेव चौहान (ऊपर) और लिली थॉमस (ऊपर) के मामलों में,

न्यायालय के समक्ष प्रश्न था, किसी निर्णय की समीक्षा की शक्ति का दायरा

इस न्यायालय की धारा 114 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत,

सी. पी. सी. का आदेश XLVII और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का आदेश XL नियम 1,

1966 .

एक्स पार्टी पिनोचेट उगार्ते (नंबर 2) (सुप्रा) के मामले में, नवंबर को 25 , 1998 हाउस ऑफ लॉर्ड्स बहुमत से 3: 2 गिरफ्तारी का पुनर्स्थापित वारंट सीनेटर पिनोशे जो चिली राज्य के प्रमुख थे और उन्हें खड़ा होना था कुछ कथित अपराधों के लिए स्पेन में मुकदमा। बाद में पता चला कि एक लॉ लॉर्ड्स (लॉर्ड हॉफमैन), जिन्होंने मामले की सुनवाई की, के साथ संबंध थे . एमनेस्टी इंटरनेशनल (ए. आई.) जो इस मामले में एक पक्ष बन गया था। सदन द्वारा मामले की सुनवाई के समय उनके द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया था।

पिनोचेट उगार्ते ने इस तथ्य के बारे में पता चलने पर इस पर पुनर्विचार करने की मांग की

पक्षपात की उपस्थिति के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उक्त निर्णय वास्तविक पूर्वाग्रह नहीं है। एक न्यायाधीश की सुनवाई के लिए अयोग्यता के सिद्धांत पर पक्षपात की उपस्थिति के आधार पर यह बताया गया था,

" यह सिद्धांत कि एक न्यायाधीश को स्वतः सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया गया था

उसके अपने मामले में एक मामला उन मामलों तक ही सीमित नहीं था जिनमें उसने परिणाम में एक आर्थिक हित, लेकिन उन मामलों पर भी लागू होता है जहाँ

न्यायाधीश के निर्णय से एक ऐसे कारण को बढ़ावा मिलेगा जिसमें आर. यू. पी. ए. अशोक हुरा  
"।

अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे] 1029

न्यायाधीश एक पक्ष के साथ शामिल था। इसका मतलब यह नहीं था कि न्यायाधीश दान से संबंधित मामलों पर नहीं बैठ सकते थे जिनके काम में वे शामिल थे, और न्यायाधीश आम तौर पर खुद को अलग करने या पक्षकारों को उस स्थिति का खुलासा करने के लिए चिंतित होंगे जहां उनकी ट्रस्टी या एक दान के निदेशक के रूप में सक्रिय भूमिका थी जो मुकदमे में एक पक्ष के साथ निकटता से संबद्ध और कार्य कर रहा था। तत्काल मामले में, तथ्य असाधारण थे कि ए. आई. अपील का एक पक्ष था, इसे एक विशेष परिणाम के लिए बहस करने के लिए जोड़ा गया था और लॉ लॉर्ड ए. आई. से निकटता से संबद्ध एक दान के निदेशक थे और अपने उद्देश्यों को साझा कर रहे थे। तदनुसार, उन्हें स्वतः ही अपील की सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसलिए याचिका मंजूर की जाएगी और मामला

प्रति प्रश्न पुनः सुनवाई के लिए सदन की एक अन्य समिति को भेजा गया।

पूर्व आदेश में किसी भी अन्याय को सुधारने के लिए सदन की अधिकारिता के बिंदु पर, यह देखा गया था:

" सैद्धांतिक रूप से यह होना चाहिए कि आपके प्रभुओं के पास, अपील की अंतिम अदालत के रूप में, पहले के आदेश के कारण हुए किसी भी अन्याय को सुधारने की शक्ति हो

इस घर से। इस संबंध में सदन की अधिकारिता पर कोई प्रासंगिक वैधानिक सीमा नहीं है और इसलिए यह अंतर्निहित है। अधिकार क्षेत्र निरंकुश बना हुआ है। कैसेल एंड कंपनी में लिमिटेड बनाम ब्रूम, (संख्या 2) [1972] 2 सभी ई. आर. 849 = 1972 ए. सी. 1136 आपके लॉर्डशिप्स ने उन परिस्थितियों में सदन द्वारा पहले से किए गए खर्चों के लिए एक आदेश में बदलाव किया जहां पक्षों को इस मुद्दे पर तर्क देने का उचित अवसर नहीं मिला था।

और यह आयोजित किया गया था,

" हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक अपील केवल तभी फिर से खोली जाएगी जब एक पक्ष को बिना किसी गलती के अनुचित प्रक्रिया के अधीन किया गया हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय को केवल इसलिए बदला या रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि बाद में इसे गलत माना जाता है।

हम यहाँ देख सकते हैं कि राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी (ऊपर) और पूर्व पक्ष पिनोचेत उगारते (नंबर 2) (ऊपर) को छोड़कर इन मामलों में, सवाल यह था कि किन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती मूल्य वाले पूर्ववर्ती निर्णय में अनुपात को समाप्त किया जा सकता है। उपरोक्त में

दो मामलों में निर्णय क्रमशः संघीय न्यायालय और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंतिम फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाले एक आवेदन पर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XL नियम 1 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 137 के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा की शक्ति [2002] 2 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1030

इस न्यायालय में, इसके अंतिम निर्णय के खिलाफ एक समीक्षा याचिका पर विचार करने में समस्या

निर्णय जिसका इसके पूर्ववर्ती-संघीय न्यायालय-को सामना करना पड़ा, उत्पन्न नहीं हुआ इस न्यायालय के समक्ष।

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता अंतिम पर फिर से विचार करने की मांग करते हैं।

पुनरीक्षण याचिकाओं में असफल होने के बाद इस न्यायालय के निर्णय

और इसमें कि ये मामले ऊपर उल्लिखित मामलों से अलग हैं। द.

उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश एक्सएल नियम 5 का प्रावधान आगे रोकता है

उसी मामले में समीक्षा के लिए आवेदन। अदालत की चिंता अब है क्या अंतिम निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को कोई राहत दी जा सकती है

इस न्यायालय का निर्णय, हालांकि समीक्षा याचिकाओं के निपटारे के बाद, शिकायत

न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और अपरिवर्तनीय अन्याय। एक राज्य में

भारत की तरह, कानून के शासन द्वारा शासित, कानून की निश्चितता घोषित और अंतिम

उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच एक सूची में गुण-दोष के आधार पर दिया गया निर्णय

देश में इसका सर्वोपरि महत्व है। अंतिमता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है

इस आधार पर नहीं कि शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय त्रुटिहीन है

लेकिन मैक्सिम पर "ब्याज का पुनः प्रकाशन समाप्त हो जाता है।"

एक समय में टकटकी के निर्णय के सिद्धांत का पालन इतना कठोर था

अंग्रेजी न्यायशास्त्र द्वारा शासित न्यायालयों में अनुसरण किया गया जो प्रस्थान करते हैं पहले की एक मिसाल से इसे विधर्म माना जाता था। घोषणा के साथ

इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अभ्यास कथन था

ऐसा करना सही प्रतीत होने पर पिछले निर्णय से हटने में सक्षम।

न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगला कदम इसकी समीक्षा करना था

अन्याय को ठीक करने के लिए अंतर-पक्षीय निर्णय। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, हम पहले ही ऊपर इंगित कर चुके हैं कि इसे शक्ति प्रदान की गई है -

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करें। की भूमिका

न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या और घोषणा करने के लिए अतीत की अवधारणा थी। यह अब बहस के लिए खुला नहीं है क्योंकि यह उचित रूप से तय है कि अदालतें ऐसा कर सकती हैं।

समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल और अनुकूल होने के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को तैयार करने वाले कानून को ढालना और निर्धारित करना, अंतिम

उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। हाल के वर्षों में अंतिम अदालतों के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव आया है कि वे अपने सामने प्रस्तुत तथ्यों पर न्याय प्रदान करने के पक्ष में हैं, बिना निरस्त किए, लेकिन निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत को पारित करके। भारत संघ और ए. एन. आर. आदि वी। एलआरएस द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)। आदि। , [ 1989 ] 2 एस. सी. सी. 754 पाठक, मुख्य न्यायाधीश। के लिए बोलते हैं संविधान पीठ ने उचित रूप से कहा:

" लेकिन सभी सिद्धांतों की तरह मनुष्य द्वारा विनियमन के लिए विकसित किया गया

7 . यह राज्य को चिंतित करता है कि मुकदमों का अंत हो। यह राज्य के हित में है कि

कानूनी मुकदमे का अंत होना चाहिए।

रूपा अशोक हुर्रा "। अशोक हुर्रा [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1031

सामाजिक व्यवस्था, बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत इसके शासन में बोधगम्य सीमाओं, संदर्भ द्वारा उत्पन्न सीमाओं द्वारा सीमित है।

एक बदलते समाज में पुनः समायोजन की आवश्यकता के लिए, एक बदले हुए सामाजिक संदर्भ द्वारा मांगे गए कानूनी मानदंडों का पुनः समायोजन। समाज में नए आग्रहों के लिए कानून को अपनाने की यह आवश्यकता समाज की सच्चाई को घर लाती है।

होम्सियन सूत्र कि "कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है, यह अनुभव रहा है" (ओलिवर वेंडेल होम्स: द कॉमन लॉ, पृष्ठ 5), और फिर जब उन्होंने एक अन्य अध्ययन में घोषणा की (ओलिवर वेंडेल होम्स: सामान्य वाहक और सामान्य कानून, (1943) 9 कर्र एल. टी. 387,388) कि "कानून हमेशा एक छोर पर जीवन से नए सिद्धांतों को अपना रहा है", और दूसरी ओर पुराने सिद्धांतों को "धीमा" कर रहा है। होम्स ने जो कहा था, उसके वैचारिक महत्व को समझाते हुए जूलियस स्टोन ने विस्तार से बताया कि मौजूदा कानूनी प्रस्तावों पर तर्क के संचालन के बजाय, परिसर के रूप में काम करने के लिए अनुभव से उभरने वाले नए अतिरिक्त-कानूनी प्रस्तावों की शुरुआत या प्रतिस्पर्धी कानूनी प्रस्तावों के बीच अनुभव-निर्देशित विकल्प से कानून का विकास होता है।

निर्धारित किया जाना है (जूलियस स्टोन: कानूनी प्रणाली और वकीलों का तर्क,

पीपी। 58-59 ) . "

किसी मामले में न्याय प्रदान करने के लिए इस न्यायालय की चिंता उसके निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों का सामना कर रहे हैं-अंतिम उपाय के न्यायालय के फैसले की निश्चितता और अंतिमता सुनिश्चित करना और इस आधार पर किसी फैसले पर पुनर्विचार करने पर न्याय प्रदान करना कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले न्यायाधीश द्वारा मामले में किसी पक्ष के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं करने या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण पूर्वाग्रह की आशंका के लिए गुंजाइश देना है। इस तरह का निर्णय, अंतिमता सुनिश्चित करने की जगह, हमेशा अनिश्चितता के बादल के नीचे रहेगा। केवल सर्वशक्तिमान ही पूर्ण न्याय का वितरक है- एक ऐसी अवधारणा जो विवादित नहीं है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा विवादित है। हमारा विचार है कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से मानवीय दोषपूर्णता की सीमा के अधीन, फिर भी दुर्लभतम मामलों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके बारे में शिकायत किए गए न्याय की सही विफलता निर्धारित करने के लिए अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामले में त्रुटि को सुधारना न केवल उचित होगा, बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से भी अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पर अपना चिंतित विचार देने के बाद हमें यह मानने के लिए राजी किया जाता है कि इन दुर्लभतम मामलों में न्याय करने का कर्तव्य निर्णय की निश्चितता की नीति पर हावी होना होगा जैसे कि यह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित में है कि देश में अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती देने के लिए खुला नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार करना 1032 होगा।

[ 2002 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्याया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है ओहायो  
पावर कंपनी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका (ऊपर)। उस मामले में न्यायालय ने

कर की वापसी के लिए निर्णय में दर्ज किए गए दावों का, कथित रूप से अधिक भुगतान किया गया है,  
कर दाता के पक्ष में। सरकार के आवेदन पर एक रिट

उस फैसले के खिलाफ प्रमाण पत्र को संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

अक्टूबर 1955 में राज्य। सरकार ने मामले की फिर से सुनवाई की मांग की

एक अन्य आवेदन दायर करना जिसे दिसंबर 1955 में खारिज कर दिया गया था। एक सेकंड

सुनवाई के लिए याचिका भी मई 1956 में खारिज कर दी गई थी। हालांकि, जून 1956 में

दिसंबर 1955 में पारित आदेश को अलग कर दिया गया था।

प्रस्ताव) और उस मामले की सुनवाई दो अन्य लंबित मामलों के साथ करने का आदेश दिया गया था

जिन मामलों में एक ही प्रश्न प्रस्तुत किया गया था। उन दो मामलों में उच्चतम न्यायालय ने करदाता के  
खिलाफ निर्णय दिया और उसके अधिकार पर

निर्णय ने दावा न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। न्यायालय के चार विद्वान सदस्यों ने, कुरियम राय के  
अनुसार, निर्णय को "निर्णय की अंतिमता में रुचि के आधार पर, जहां न्याय के हित की आवश्यकता है, वहां  
परिणाम देना चाहिए"। तीन विद्वान सदस्यों ने असहमति जताई और कहा कि प्रमाणपत्र से इनकार अंतिम हो  
गया है और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, दो विद्वान सदस्यों ने भाग नहीं लिया।

इस न्यायालय ने हरबंस सिंह के मामले (ऊपर) में, एक आवेदन पर

विशेष अनुमति याचिका और समीक्षा को खारिज करने के बाद दायर संविधान के अनुच्छेद 32 ने अपने  
फैसले पर पुनर्विचार किया। उस मामले में, अन्य लोगों के अलावा, याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को  
आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। शेष दो दोषियों में  
से एक के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। याचिकाकर्ता  
की मौत की सजा पर रोक लगाते हुए, ए. एन. सेन, जे. ने अपनी सहमति वाली राय में, याचिकाकर्ता की  
विशेष अनुमति, समीक्षा याचिकाओं और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को खारिज करने पर ध्यान दिया और  
कहा;

" इस न्यायालय को उचित और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

न्याय का उचित प्रशासन। अधिकारिता और शक्तियों के अलावा

संविधान के अनुच्छेद 32 और 136 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त,

मेरी राय है कि यह न्यायालय एक अंतर्निहित धारणा को बरकरार रखता है और उसे बनाए रखना चाहिए।

में किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए शक्ति और अधिकार क्षेत्र

न्याय के प्रशासन के बड़े हित और रोकथाम के लिए

प्रकट अन्याय किया जा रहा है। यह शक्ति अनिवार्य रूप से संयम से होनी चाहिए।

के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है

न्याय "।

अंतुले के मामले (ऊपर) में, सात में बहुमत-आर. यू. पी. ए. की न्यायाधीश पीठ अशोक हुर्रा

बनाम।

अशोक हुरी [सैयद शाह मोहम्मद कादरी, जे.] 1033

इस न्यायालय ने एक संपार्श्विक कार्यवाही में संविधान पीठ के पहले के एक फैसले को इस विचार पर दरकिनार कर दिया कि यह आदेश 1952 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था; उस अधिनियम की पृष्ठभूमि में बिना पूर्ववर्ती और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, जिसे पूर्व-ऋण सुधारने की आवश्यकता थी।

न्याया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक आवेदन पर, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया

यह घोषणा करते हुए कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित बार परिषदों की अनुशासनात्मक समितियों के पास ही किसी अधिवक्ता को पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए कानून का अभ्यास करने से निलंबित करने या प्रतिबंधित करने का विशेष अधिकार क्षेत्र था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के पास अपनी अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उस संबंध में ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र, शक्ति या अधिकार नहीं था। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर पुनः विचार किया: विनय चंद्र मिश्रा, [1995] 2 एससीसी 584। इस न्यायालय के विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या

इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी अधिवक्ता को प्रैक्टिस करने से रोकने और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उसका लाइसेंस निलंबित करने की सजा दी जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के साथ अनुच्छेद 142 के तहत पढ़ा जाता है। वहाँ एक दोषी वकील को आपराधिक अवमानना का दोषी पाया गया और उसे छह सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए इस न्यायालय के फैसले की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से भी निलंबित कर दिया गया। उस सजा के परिणामस्वरूप एक वकील के रूप में उनकी क्षमता में उनके द्वारा रखे गए सभी निर्वाचित और नामित पदों/पदों को उन्हें खाली करना पड़ा। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति की उपचारात्मक प्रकृति के दायरे को स्पष्ट करते हुए, यह देखा गया:

" संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की पूर्ण शक्तियाँ न्यायालय में निहित हैं और इन शक्तियों के पूरक हैं।

वे शक्तियाँ जो विशेष रूप से विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को प्रदान की जाती हैं, हालाँकि उन कानूनों द्वारा सीमित नहीं हैं। ये शक्तियाँ पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से कानूनों से स्वतंत्र भी मौजूद हैं। ये शक्तियाँ बहुत व्यापक आयाम की हैं और पूरक शक्तियों की प्रकृति में हैं। यह शक्ति कानूनों के अलावा अधिकार क्षेत्र के एक अलग और स्वतंत्र आधार के रूप में मौजूद है। यह नींव पर खड़ा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में अन्याय को रोकने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इसके अभ्यास के लिए आधार को एक अलग और शायद व्यापक आधार पर रखा जा सकता है।

इस प्रकार, यह पूर्ण अधिकार क्षेत्र शक्ति का अवशिष्ट स्रोत है जो [2002] 2 एस. सी. आर.

1034

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय जब भी न्यायसंगत हो, आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप कर सकता है। और ऐसा करने के लिए न्यायसंगत और विशेष रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए विधि की उचित प्रक्रिया, कानून के अनुसार न्याय का प्रशासन करते हुए। यह अपरिहार्य है अन्य सभी शक्तियों से संबद्ध है और अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध से मुक्त है। और सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में एक मूल्यवान हथियार के रूप में काम करता है "न्याय की धारा में रुकावट या बाधा" को रोकने के लिए।

पीठ ने यह विचार रखा कि अधिवक्ता को प्रैक्टिस से निलंबित करना और उनके लाइसेंस को निलंबित करना उक्त के तहत शक्ति के दायरे में नहीं था

अनुच्छेद और आर. वी. सी. मिश्रा के मामले (ऊपर) में फैसले को खारिज कर दिया।

एम. एस. अहलावत के मामले में (ऊपर), याचिकाकर्ता, जिसे दोषी पाया गया था

जाली हस्ताक्षर करना और इससे पहले विभिन्न चरणों में गलत बयान देना

इस न्यायालय को अफजल बनाम में आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत सजा दी गई थी। राज्य हरियाणा का, [1996] 7 एस. सी. सी. 397। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन दायर किया।

उस आदेश की वैधता का उल्लेख करने वाला संविधान। ध्यान में रखते हुए उसके आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय की विफलता की शिकायत

कारावास जिसने उनका करियर बर्बाद कर दिया, बिना अधिकार क्षेत्र के या बिना कार्य करते हुए

कोई पुण्य नहीं था, लेकिन इसे ठीक करना न्यायिक विवेक की मजबूरी थी। द. निर्णय की शुद्धता की जांच की गई और त्रुटि को ठीक किया गया।

ऊपर चर्चा किए गए मामलों में इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों पर पुनर्विचार किया,

अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 129 और 142 के तहत जो इस पर बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं।

न्यायालय पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करे। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं

उस से ऊपर एक अदालत के रूप में अनुच्छेद 129 के तहत इस अदालत की शक्ति का दायरा

अभिलेख और अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति की सीमा तक विज्ञापित  
संविधान।

हमारे विचार में चर्चा का परिणाम यह है कि इस न्यायालय को रोकने के लिए

इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय की घोर विफलता को ठीक करने के लिए, अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए इसके निर्णयों पर फिर से विचार किया जा सकता है।

अगला कदम इस तरह के उपचार के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है।

इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के तहत याचिका ताकि अंतर्निहित शक्ति के तहत एक उपचारात्मक याचिका की आड़ में निश्चित रूप से दूसरी समीक्षा याचिका दायर करने के लिए दरवाजे नहीं खोले जा सकें। यह सामान्य आधार है कि जब बहुत मजबूत कारण मौजूद हों, तो न्यायालय को इस न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए, जो 1035 को अंतिम हो गया है।

रूपा अशोक हुर्रा बनामा अशोक हुर्रा [बनर्जी, जे.]

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना। उन सभी आधारों को गिनना न तो उचित है और न ही संभव है जिन पर ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है।

फिर भी, हम सोचते हैं कि एक याचिकाकर्ता पूर्व ऋण राहत का हकदार है

न्याय्यता यदि वह यह स्थापित करता है कि (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन इस आधार पर किया गया है कि वह एल. आई. एस. का पक्षकार नहीं था, लेकिन निर्णय ने उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला या, यदि वह एल. आई. एस. का पक्षकार था, तो उसे कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई और मामला इस तरह आगे बढ़ा जैसे कि उसने नोटिस दिया हो और (2) जहां कार्यवाही में एक विद्वान न्यायाधीश विषय-वस्तु या पक्षपात की आशंका के लिए गुंजाइश देने वाले पक्षों के साथ अपने संबंध का खुलासा करने में विफल रहा और निर्णय याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

याचिकाकर्ता, उपचारात्मक याचिका में, विशेष रूप से यह स्पष्ट करेगा कि -

उसमें उल्लिखित आधार समीक्षा याचिका में लिए गए थे और यह कि परिसंचरण द्वारा खारिज कर दिया गया। उपचारात्मक याचिका में एक प्रमाणन होगा

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा।

हमारा विचार है कि चूंकि मामला एक की पुनः परीक्षा से संबंधित है

इस न्यायालय का अंतिम निर्णय, हालांकि सीमित आधार पर, उपचारात्मक याचिका

इसे पहले तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए-अधिकांश न्यायाधीश और

फैसला देने वाले न्यायाधीशों ने शिकायत की, यदि उपलब्ध हो। केवल तभी जब

इस पीठ के अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों का निष्कर्ष है कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है कि इसे उसी पीठ (जहां तक संभव हो) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो उचित आदेश पारित कर सकती है। सुधारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी चरण में पीठ के लिए यह खुला रहेगा कि वह किसी वरिष्ठ वकील से उसकी सहायता करने के लिए कहे।

न्यायमित्र। पीठ द्वारा किसी भी स्तर पर यह अभिनिर्धारित करने की स्थिति में कि याचिका बिना किसी योग्यता और कष्टप्रद के, यह अनुकरणीय लागत लगा सकता है

याचिकाकर्ता।

जहाँ तक वर्तमान रिट याचिकाओं का संबंध है, रजिस्ट्री

उन्हें संसाधित करें, इसके बावजूद कि उनमें यह कथन नहीं है कि

पुनर्विचार याचिकाओं और याचिकाओं में आग्रह किए गए आधारों को विशेष रूप से लिया गया था

प्रचलन में खारिज कर दिए गए।

तदनुसार बिंदु का उत्तर दिया जाता है।

बनर्जी, जे. मुझे एक बहुत ही सरल दौर से गुजरने का सौभाग्य मिला है।

भाई कादरी द्वारा राय की अभिव्यक्ति और उसके साथ अपनी सहमति दर्ज करते हुए मैं अपने स्वयं के कुछ पैराग्राफ जोड़ना चाहता हूँ।

यह मुद्दा वर्तमान में शामिल है, हालांकि [2002] 2 एस. सी. आर. के दायरे में एक अवधारणा नहीं है।

1036

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टकटकी निर्णय का सिद्धांत लेकिन दायरे के रूप में प्रभाव के समान या घटनाओं के सामान्य क्रम में इस न्यायालय के निर्णय की अंतिमता। वहाँ।

संभवतः किसी भी तरह से संदेह नहीं हो सकता है कि मामले को एक बार द्वारा निपटा गया था

इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की शक्ति और अनुच्छेद 137 और 145 के प्रावधान इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। घटना में,

हालांकि, एक पक्ष समीक्षा की अस्वीकृति के कारण व्यथित है,

यह सवाल उठाया गया कि क्या इसके वादी को सभी के लिए हमले का सामना करना पड़ेगा

आने वाले समय और निरंतरता में जब आदेश के सामने यह प्रतीत होता है

पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में एक पूर्वाग्रह या घोर या प्रकट अन्याय होने का तथ्य, जो सदमे में डाल देता है

एक समझदार व्यक्ति का विवेक: यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि तथ्य, जैसा कि देखा गया है

ऊपर, न केवल अनुचित हैं बल्कि संभवतः असंभवता के क्षेत्र में हैं

या अधिक उचित रूप से असंभव।

श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ परिषद के समर्थन में उपस्थित हुए

इस पीठ के समक्ष मामलों में से एक, अपने मामले में काफी जोरदार रहा है।

पक्षपात की आशंका के संबंध में प्रस्तुतियाँ और यह उनका तर्क है कि केवल पक्षपात की संभावना इस न्यायालय को आगे की अनुमति देने के लिए प्रेरित करेगी।

मामले पर विचार करें। संयोग से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन सभी मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। हमने कुछ मामलों में अभिलेख मांगे, जो इस न्यायालय के निर्णयों से समाप्त होते हैं और इस प्रकार मुख्य मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका की स्थिरता के रूप में उत्पन्न होता है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए इस न्यायालय का रुख करने का अधिकार मौजूद है और यह अनुच्छेद 32 के संदर्भ में प्रदान किया गया है और इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा व्यापक संभव विस्तार की है, लेकिन जहां तक रिट जारी करने का संबंध है, यह विचार नकारात्मक रूप से अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है।

लगभग चार दशक पहले, नरेश श्रीधर मिराजकर और ओआरएस में। वी. राज्य

महाराष्ट्र और अन्न. , [ 1966 ] 3 एस. सी. आर. 744, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र की उपलब्धता को बिना किसी अनिश्चितता के नकार दिया और अभिव्यक्ति की अत्यंत स्पष्टता और आनंद के साथ कहा:

" अतः हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जहाँ तक इस अधिकार क्षेत्र का संबंध है। प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए न्यायालय का संबंध है, आर. यू. पी. ए. अशोक हुर्ना बनाम के लिए असंभव है।

अशोक हुर्रा [बनर्जी, जे.]

1037

उनके समक्ष लंबित कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उच्च न्यायालय हैं -  
उक्त अधिकारिता का प्रयोग करके उसे ठीक किया जा सकता है। हम.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना अनुचित होगा

सुधार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा  
इस काल्पनिक परिकल्पना पर ऐसे न्यायिक आदेश कि उच्च न्यायालय कर सकते हैं

इससे पहले लंबित मामलों में या उनके संबंध में अतिरंजित आदेश पारित करना

और यह कि प्रमाण पत्र के माध्यम से एक उपाय, इसलिए,  
के दायरे में शामिल किए जाने की मांग की जाए और माना जाए

अनुच्छेद 32. अनुच्छेद 32 में उपयोग किए गए शब्द निस्संदेह व्यापक हैं; लेकिन

उन विचारों को ध्यान में रखते हुए जो हमने निर्धारित किए हैं  
उनके निर्णय के दौरान, हम संतुष्ट हैं कि विवादित आदेश

इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं लाया जा सकता है

अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र का एक रिट जारी करना; अन्यथा अभिनिर्धारित करना होगा  
अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सीमाओं के प्रतिकूल जिसके भीतर

सर्टिओरारी के रिट जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है और  
असंगत है उक्त के  
संबंध में इस न्यायालय के फैसलों की समान प्रवृत्ति के साथ

बिन्दु "।

दो दशक बाद, यह न्यायालय ए. आर. अंतुले बनाम. आर. एस. नायक और अन्न। ,

[ 1988 ] 2 एस. सी. सी. 602, नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मिराजकर मामले में निर्णय को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि इस न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है और यह इस तथ्य के कारण है कि इस न्यायालय की पीठें इसकी बड़ी पीठों के अधीन नहीं हैं और इस प्रकार न्यायालय के न्यायिक पक्ष में दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं है। श्रीमती में। त्रिवेणीबेन बनाम. गुजरात राज्य, [1989] 1 एस. सी. सी. 678, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने भी बिना किसी अनिश्चितता के यह निर्धारित किया कि यह इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम फैसले की जांच करने के लिए खुला नहीं होगा। हालाँकि, सूची को पूरा करने के लिए, अजीत कुमार बारात बनाम मामले में इस न्यायालय का एक बहुत ही हालिया निर्णय। सचिव, भारतीय चाय संघ और अन्या। , [ 2001 ] 5 एस. सी. सी. 42

हममें से एक (शिवराज वी. पाटिल, जे.) मिराजकर (ऊपर) और अंतुले (ऊपर) के विचार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अधिकार इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस प्रकार कोई संदेह नहीं है कि

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परिकल्पित रिट अधिकार क्षेत्र की उपलब्धता की याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि कानून [2002] 2 एस. सी. आर. पर अच्छी तरह से तय हो गया है।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1038

इस अंक में और इस तरह हमें आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

उस पर।

[

उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, क्या इसका अर्थ है और

यह एक बंद दरवाजे का संकेत देता है, भले ही इस न्यायालय के आदेश में यह दर्शाया गया हो कि प्रकृतिक न्याय का प्रतिकूल और गंभीर रूप से उल्लंघन करता है

पक्षों के अधिकार या वही आदेश को प्रस्तुत करने वाले प्रकट अन्याय को दर्शाते हैं।

न्याय का उपहास-क्या यह कहा जा सकता है कि किसी आदेश की बाध्यकारी प्रकृति

इस न्यायालय को इस प्रकार कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है, भले ही यह दुर्गम हो

कठिनाई और भारी सार्वजनिक चोट-बहस बहुत बड़ी और व्यापक है।

प्रभाव और इस प्रकार से सावधानी से निपटना होगा और

इसके प्रभाव के संबंध में सावधानी और उचित सावधानी के साथ-प्रमुख

आधार न्याय की अवधारणा है और यही वह जगह है जहाँ पूर्व ऋण का सिद्धांत है।

न्याय खेलने के लिए आता है। क्या यह कहा जा सकता है कि देश की न्याय वितरण प्रणाली ऐसी है कि जनहित के उल्लंघन को नोटिस करने के बावजूद

सामाजिक प्रभाव के अनुरूप, यह न्यायालय एक सुखद स्थिति बनाए रखेगा  
यहाँ तक कि समाज के रोने के लिए अंधी आँखों और बहरे कानों के साथ मौन

आम तौर पर या

इस द्वारा पारित आदेश की अंतिमता के आधार पर वादी का

अदालत? यह सच है कि अंतिमता को बनाए रखना होगा लेकिन क्या यह प्रमुख है?

कानून किस आवश्यकता की परिकल्पना करता है? बचाव पाउंड ने कहा कि लचीलापन

कानून का सबसे बड़ा गुण है और इस प्रकार इसकी प्रयोज्यता भी लचीली होनी चाहिए।

एक सख्त प्रारूप पर एक कठोर आग्रह के बजाय। स्थिति का न्याय होगा  
अवधारणा के बारे में उचित धारणा के साथ विचार किया जाना चाहिए

इस तरह की

के साथ। एक पलक झपकाते हुए प्रकाश का ध्यान एक व्यापक सामाजिक स्थिति पर केंद्रित होना चाहिए। चूंकि कानून समाज के लिए है और यदि लचीलापन इसका गुण है,

किस कानून को लाभ होता है, इस प्रकार इसका संबंधित प्राथमिक कर्तव्य परिवर्तन करना होगा

उचित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साथ कानूनी क्षितिज और दृष्टिकोण। कानून को समाज को छोड़ने के बजाय समाज का पालन करना चाहिए और बिना किसी विचलन के या सामाजिक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न किए बिना सख्त रास्ते पर चलना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप एक सामाजिक तबाही का सामना करना पड़ता है।

लॉर्ड डेनिंग द्वारा ए/एस में 'एक्स डेबिटो जस्टिटिया' सिद्धांत की व्याख्या

कैथरीनहोल्म बनाम। नॉरक्रिपमेंट ट्रेडिंग लिमिटेड, (1972) 2 ऑल ई. आर. 538 को बल्कि प्रतिबंधात्मक कहा गया है, लेकिन चूंकि मूल रूप से न्याय की अवधारणा पर यही बात सामने आती है, इसलिए अपने लिए बोलते हुए इस तरह की आलोचना को स्वीकार न करें। मास्टर ऑफ द रोल्स ने कहा कि यदि निर्णय अनियमित है-यानी, जिस पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए थे, तो प्रतिवादी को इसे अलग रखने का अधिकार है, लेकिन यदि यह अन्यथा नियमित है, तो निर्णय को अलग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालाँकि, इसके बाद नियमित और 1039 के सही प्रभाव के बारे में सवाल उठता है।

रूपा अशोक हुर्रा बनामा अशोक हुर्रा [बनर्जी, जे.]

अनियमित निर्णय: चूँकि इस मुद्दे पर बहुत व्यापक बहस होती है, इसलिए हम अंग्रेजी न्यायालयों और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा सिद्धांत के आगे के उच्चारण को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थों को बताने या शब्दावली के प्रभावों पर विस्तार करने से खुद को रोकते हैं।

अतः उक्ति के वास्तविक उद्देश्य की ओर मुड़ते हुए, यह कोई लाभ नहीं है।

कि यही न्याय की अवधारणा से संबंधित है और उससे उत्पन्न होता है: यदि अवधारणा का उल्लंघन प्रतीत होता है, तो एक मोड़ होने और इस तरह कानूनी अदालतों द्वारा पूरी तरह से मौन बनाए रखने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसी आधार पर न्यायमित्र के रूप में उपस्थित भारत के विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है। यद्यपि हम इस न्यायालय के आदेश को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताने के लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन न्याय के उद्देश्यों के लिए अंतर्निहित शक्ति की उपलब्धता के तथ्य को किसी भी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है, जिसमें कानून की सर्वोच्चता प्रदान की गई है, जिसका तर्क न्याय है। द.

इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XL VII नियम 6 द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, जो नीचे दिया गया है:

" 6. इन नियमों में कुछ भी सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ जो हो सकती हैं

न्याय के उद्देश्य के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक

}

अदालत से "।

ए. आर. अंतुले (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियों से सहमति मिलती है।

इस न्यायालय द्वारा इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए। इस न्यायालय के संज्ञान में कोई त्रुटि लाए जाने की स्थिति में न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ए. आर. अंतुले (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 40 में न्यायाधीश मुखर्जी (जैसा कि वे तब थे) ने बहुत स्पष्ट रूप से और अत्यंत सटीकता के साथ कहा:

" हालाँकि, वैधता का सवाल महत्वपूर्ण है कि

अधिकारिता केवल एक उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की जा सकती है और वह,

अभ्यास, किसी भी निर्णय को किसी भी हीन द्वारा संपार्श्विक रूप से अभिशंसन नहीं किया जा सकता है

अदालत। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय हमेशा अपनी गलती सुधार सकता है।

या तो याचिका के माध्यम से या पूर्व ऋण न्याय्यता के माध्यम से इसके नोटिस के लिए। देखें।

रुबिनस्टीन की न्यायपालिका और अवैधता) "।

संयोग से सिंथेटिक्स में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ और [2002] 2 एस. सी.

आर.

1040

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य , [ 1990 ] 1 एस. सी. सी. 109 ने ओस्टाइम (कर निरीक्षक) v में लॉर्ड डेनिंग के एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया। ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल प्रोविडेंट सोसाइटी, (1959) 3 ऑल ई. आर. 245 1960 ए. सी. 459 और मैसाचुसेट्स एट अल वी के राष्ट्रमंडल के मामले में न्यायमूर्ति जैक्सन द्वारा असहमति को नोट करना। यू. एस. ए. (92 एल. एड. 968), जिसमें समान स्वर में यह कहा गया है कि जैसे ही किसी को गलत दिशा में यात्रा मिलती है, हमेशा सही दिशा की ओर मुड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि कानूनी अदालतों को हर समय गलत के बजाय सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्निहित शक्ति के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, एस नागराज और अन्य मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। वी. कर्नाटक राज्य और अन्न , [ 1993 ] सप. 4 एस. सी. सी. 595

यह काफी उपयुक्त लगता है। इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 में, न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों पर भरोसा करने पर कि न्याय सबसे ऊपर है, नीचे कहा गया है:

" शाब्दिक रूप से और यहां तक कि न्यायिक रूप से समीक्षा का अर्थ है पुनः परीक्षा या पुनः परीक्षा।  
विचार करें।  
इसमें अंतर्निहित बुनियादी दर्शन सार्वभौमिक है।

और यहां तक कि कानून भी निर्णय की अंतिमता के पक्ष में दृढ़ता से झुकते हैं कानूनी और उचित रूप से बनाया गया। वैधानिक और न्यायिक दोनों तरह से अपवाद

आकस्मिक गलतियों या गर्भपात को ठीक करने के लिए तराशा गया है या

न्याय। यहां तक कि जब कोई वैधानिक प्रावधान और कोई नियम नहीं थे

जिसे वह अपने आदेश में सुधार कर सकता था, अदालतों ने ऐसी शक्ति को समाप्त कर दिया प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता से बचें। राजा पृथ्वी में

चंद लाल चौधरी बनाम। सुखराज राय, आकाशवाणी (1941) एफ. सी. 1,2: 1940

एफसीआर 78 (1941) 1 एमएलजे सप। 45 न्यायालय ने कहा कि यहां तक कि

यद्यपि उच्चतम न्यायालय को अनुमति देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे

इसके आदेश की समीक्षा करें फिर भी यह सीमित और संकीर्ण आधार पर उपलब्ध था

प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विकसित। अदालत ने

राजंदर में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी दी गई

नारायण राय बनाम। विजय गोविंद सिंह, (1836) 1 मू पीसी 117: 2 एमआईए

181 : 1 धारा 175 कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतिम था और हो सकता था बदला नहीं जाएगा:

' ... ..... फिर भी, यदि निर्णयों को मूर्त रूप देने में गलतफहमी से, त्रुटियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इन न्यायालयों के पास है, समान विधि, वही शक्ति जो अभिलेख न्यायालय और

कानून में उन गलतियों को सुधारना है जो सामने आई हैं। द. हाउस ऑफ लॉर्ड्स गलतियों को सुधारने की समान शक्ति का प्रयोग करता है।

अपने स्वयं के निर्णय तैयार करने में किया गया, और इस न्यायालय को एक ही अधिकार रखते हैं। हालांकि लॉर्ड्स ने 1041 रन बनाए हैं।

रूपा अशोक हुर्रा "। अशोक हुर्रा [बनर्जी, जे.]

आगे बढ़ें, और गलतियों को ठीक करें

निर्णयों के विवरण में असावधानी; या प्रदान किया है

या व्याख्यात्मक बात जोड़ दी है, या सुलह कर ली है  
विसंगतियाँ।

शक्ति के प्रयोग के लिए आधार उसी निर्णय में कहा गया था इसके अंतर्गत:

" इस पर संदेह करना असंभव है कि इस तरह के भोग में विस्तार हुआ

मामले मुख्य रूप से रोकने के लिए प्रचलित प्राकृतिक इच्छा के कारण होते हैं।  
अंतिम उपाय के न्यायालय द्वारा किया जा रहा अपरिवर्तनीय अन्याय,

जहाँ किसी दुर्घटना से, बिना किसी दोष के, पार्टी ने नहीं किया है  
सुना गया है और एक आदेश अनजाने में किया गया है जैसे कि

पार्टी को सुना गया था। "

इस प्रकार किसी आदेश का सुधार मौलिक सिद्धांत से उत्पन्न होता है।

कि न्याय सबसे ऊपर है। इसका प्रयोग त्रुटि को हटाने के लिए किया जाता है और नहीं

अंतिमता को परेशान करने के लिए। जब संविधान बनाया गया था

संविधान निर्माता जिनके पास कल्पना करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान था इस तरह के प्रावधान  
की प्रभावशीलता ने स्पष्ट रूप से मूल शक्ति प्रदान की

संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करना।

और अनुच्छेद 145 के खंड (सी) ने इस न्यायालय को नियम बनाने की अनुमति दी

उन शर्तों के लिए जिनके अधीन कोई निर्णय या आदेश हो सकता है

एक विस्तारित अर्थ दिया गया है और एक डिक्री या आदेश पारित किया गया है परिस्थितियों की  
वास्तविक स्थिति की गलत समझ के तहत आयोजित किया गया है

शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जमीन होना। ऑर्डर एक्सएल के अलावा

उच्चतम न्यायालय के नियम 1 के अनुसार इस न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति है

अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने से वर्जित है यदि वह संतुष्ट है कि न्याय के  
लिए ऐसा करना आवश्यक है। "

इसकी हालिया घोषणाओं में से एक [भारत और ए. एन. आर. पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ,  
[ 1998 ] 4 एस. सी. सी. 409] इस न्यायालय के पास [2002] 2 एस. सी. आर. है।

1042

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 129 पर भरोसा करते हुए इस मुद्दे से कुछ हद तक निपटने का अवसर। सर्वोच्च की पूर्ण शक्तियाँ

न्यायालय, जैसा कि अनुच्छेद 142 के तहत परिकल्पित है, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की उन शक्तियों के लिए पूरक है और यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 47 और 48 में है, इस न्यायालय ने कहा:

" 47. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियाँ न्यायालय में निहित हैं और उन शक्तियों के पूरक हैं जो विशेष रूप से विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई हैं।

हालाँकि कानून उन कानूनों द्वारा सीमित नहीं हैं। ये शक्तियाँ पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से कानूनों से स्वतंत्र भी मौजूद हैं। ये शक्तियाँ बहुत व्यापक आयाम की हैं और पूरक शक्तियों की प्रकृति में हैं। यह शक्ति कानूनों के अलावा अधिकार क्षेत्र के एक अलग और स्वतंत्र आधार के रूप में मौजूद है। यह नींव पर खड़ा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में अन्याय को रोकने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इसके अभ्यास के लिए आधार को एक अलग और शायद व्यापक आधार पर रखा जा सकता है। इस प्रकार, यह पूर्ण अधिकार क्षेत्र शक्ति का अवशिष्ट स्रोत है जिसे यह न्यायालय जब भी न्यायसंगत और न्यायसंगत हो और विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, कानून के अनुसार न्याय का प्रशासन करते हुए, आवश्यकतानुसार प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अन्य सभी शक्तियों के लिए एक अनिवार्य सहायक है और अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध से मुक्त है और न्याय की धारा को बाधित करने या बाधित करने से रोकने के लिए न्यायालय के हाथों में एक मूल्यवान हथियार के रूप में काम करता है। " हालाँकि, यह याद रखने की आवश्यकता है कि न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ

\*

अनुच्छेद 142 के उपचारात्मक होने के कारण इसे ऐसी शक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी कारण से निपटने के दौरान वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी करने के लिए अधिकृत करती हैं। इस शक्ति का उपयोग न्यायालय के विचाराधीन मामले या मामले पर लागू मूल कानून को "प्रतिस्थापित" करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142, इसके विस्तार की चौड़ाई के साथ भी, एक नए भवन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जिसे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक अवमानना करने वाले अधिवक्ता को दंडित करना, अदालत की अवमानना के मामले में उसके वकालत करने के लाइसेंस को निलंबित करते हुए, एक ऐसी शक्ति जो अन्यथा वैधानिक रूप से केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए उपलब्ध है।

भारत, इस आधार पर कि अवमानना करने वाला भी एक अधिवक्ता है, इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 142 के निर्माण को कार्यात्मक रूप से सूचित किया जाना चाहिए 1043



रूपा अशोक हुर्रा "। अशोक हुर्रा [वनर्जी, जे.]

लेख के हितकारी उद्देश्यों से, अर्थात् , पूर्ण न्याय करने के लिए दलों के बीच। यह अन्यथा नहीं हो सकता। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि

अदालत की अवमानना का मामला, अवमाननाकर्ता और अदालत को नहीं कहा जा सकता है मुकदमेबाजी करने वाले पक्ष होने के लिए।

48. अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय

142 ऐसा आदेश देने की शक्ति है जो करने के लिए आवश्यक है

किसी भी लंबित मामले या मामले में पक्षों के बीच पूर्ण न्याय इससे पहले "। शक्ति की प्रकृति को ही न्यायालय को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए

अपने लिए सीमाएँ जिनके भीतर उन शक्तियों का प्रयोग करना है और सामान्य रूप से

यह किसी विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान की अवहेलना नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि शायद परस्पर विरोधी दावों के बीच इक्विटी को संतुलित करने के लिए

किसी कारण या मामले में पक्षकारों को "द्विधाओं को दूर करके" मुकदमा करना

उससे पहले। वास्तव में यह न्यायालय सीमित अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है।

केवल विवाद-निपटान। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्थापित है कि यह

न्यायालय हमेशा एक कानून निर्माता रहा है और इसकी भूमिका केवल कानून बनाने से परे है।

विवाद-सेटिंग। यह एक "अस्पष्ट क्षेत्रों में समस्या-समाधानकर्ता" है के देखें

वीरास्वामी वी. भारत संघ, [1991] 3 एससीसी 655: [ 1991 ] एससीसी (सीआरआई)

734 लेकिन विषय से संबंधित मूल वैधानिक प्रावधान इस न्यायालय द्वारा किसी दिए गए मामले के मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 142 के तहत आदेश देते समय। वास्तव में, ये संवैधानिक

शक्तियों को किसी भी तरह से किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

लेकिन साथ ही इन शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब

उनका अभ्यास जो किया गया है उसके साथ सीधे संघर्ष में आ सकता है

विषय के साथ स्पष्ट रूप से निपटने वाले क़ानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है।

संयोग से, यह न्यायालय निवारण के लिए एक मार्ग के रूप में खड़ा है

शिकायत न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में बल्कि देश में प्रत्येक शिकायत के लिए एक मंच और मंच के रूप में और इस संदर्भ में श्री शांति भूषण ने कुछ याचिकाकर्ताओं के समर्थन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 50 वर्षों से अधिक की अपनी यात्रा में देश के लोगों का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जब भी इसकी आवश्यकता होती है-चाहे वह पुलिस के अत्याचार हों या सार्वजनिक शिकायत।

एक सरकारी कार्रवाई से संबंधित है जिसमें कई समस्याएं शामिल हैं। श्री शांति भूषण ने तर्क दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ लोगों को विश्वास है कि न्याय सबसे ऊपर है और वे अपने वास्तविक रूप और क्षेत्र में न्याय प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यह सभी विवादों से परे है। यह तर्क दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद कार्यवाही की अंतिमता, वहाँ

होना चाहिए, लेकिन यह इस न्यायालय को किसी आदेश के कारण हुए घोर अन्याय के लिए याचिका के तथ्य में जाने से नहीं रोकता है या नहीं कहता है

[2002] 2 एस. सी. आर. के लिए एक प्राधिकरण होने की अंतर्निहित शक्ति के तहत स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1044

अपनी त्रुटियों को ठीक करें-किसी अन्य दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए

जारी रखा। हालाँकि, यहाँ यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार खड़ा है संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में इस न्यायालय पर लागू किया गया, जैसे -

यह पहले भी देखा गया है और यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि दूसरी समीक्षा याचिका इसे बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में संदर्भ दिया जा सकता है कि

जे. रंगा स्वामी बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। सरकार. ए. पी. और

ओआरएस।, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 535, जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार कहा है:

" हमारा स्पष्ट मत है कि ये आवेदन नहीं हैं

बनाए रखने योग्य। याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, ने उल्लेख किया

अंतुले के मामले में निर्णय [1988] 2 एस. सी. सी. 602: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1531

हालाँकि, हमारी राय है कि उस मामले का सिद्धांत नहीं है

यहाँ लागू होता है। वे सभी बिंदु जिनके बारे में याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था

मूल रूप से अपील और रिट याचिकाएँ। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा कि पीठ ने उन्हें कुछ देर तक सुना। अतः यह स्पष्ट है कि

सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद मामलों का निपटारा किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया और केवल यह तथ्य कि आदेश नहीं है

दलीलों पर चर्चा करें या कारण दें जो याचिकाकर्ता को अधिकार नहीं दे सकते हैं

वास्तव में दूसरी समीक्षा क्या है "।

यह सच है कि न्यायालय की राय के संबंध में उचित सम्मान होना चाहिए

रंग स्वामी (ऊपर), लेकिन वर्तमान में स्थिति इसके आसपास केंद्रित है

यदि कोई प्रकट अन्याय होता है तो पूर्व ऋण न्याय के सिद्धांत को विशुद्ध रूप से निष्क्रियता में भूमिका निभाने या सामान्य ऊंचाइयों से ऊपर उठने के लिए कहा जाएगा क्योंकि यह उपदेश देता है कि न्याय सबसे ऊपर है। दूसरा विकल्प समाज की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के समय और वर्तमान चरण के अनुरूप प्रतीत

होता है। प्रकट अन्याय लाइलाज होने के बजाय प्रकृति में उपचार योग्य है और यह न्यायालय अपनी पवित्रता खो देगा और इस प्रकार संस्थापक पिताओं की अपेक्षाओं को विश्वास में ले लेगा कि न्याय सबसे ऊपर है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रियात्मक कानून/प्रक्रियात्मक न्याय न्याय की अवधारणा से आगे नहीं बढ़ सकता है और यदि कोई आदेश प्रकट अन्याय पैदा करने के लिए खड़ा होता है, तो क्या उसे मौन रहने दिया जाएगा ताकि पक्षकारों को हमेशा प्रभावित किया जा सके या न्याय की अवधारणा को अदालत को सक्रिय करना चाहिए ताकि समस्या के लिए गलत दृष्टिकोण को हल करने का एक तरीका खोजा जा सके। महान्यायवादी महोदय, अपने आदेश में पूरे जोर के साथ, हालांकि मुख्य रूप से इस बात पर सहमत थे कि स्थिति के न्याय पर गौर करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो राहत दी जानी चाहिए, लेकिन उसी सांस पर प्रस्तुत किया कि न्यायालय को रास्ते पर व्यापार करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा यह पेंडोरा के 1045 को खोल देगा।

रूपा अशोक हुर्रा बनाम। अशोक हुर्रा [बनर्जी, जे. जे.]

बॉक्स और इस प्रकार, यदि बिल्कुल भी हो, तो दुर्लभतम मामलों में आगे की जांच की जा सकती है। हालांकि यह सच है कि कानूनी अदालतों ने मुकदमेबाजी से खुद को बोझिल कर लिया है और उपमहाद्वीप में मामलों के निपटारे में देरी अज्ञात नहीं है और

इस न्यायालय द्वारा मामले के किसी भी आगे के मूल्यांकन की स्थिति में, यह आगे कोई देरी नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जो दूर की बात नहीं हैं, लेकिन मेरे विचार से यह स्वयं इस न्यायालय को मामले के आगे के मूल्यांकन से नहीं रोकेगा, हालांकि, यह इस तरह के अतिरिक्त मूल्यांकन के योग्य है।

खोलने के संबंध में श्री अटॉर्नी द्वारा चेतावनी का नोट

हालाँकि, सख्ती से बोलते हुए, पेंडोरा बॉक्स प्रकृति में बहुत व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में न्याय की अवधारणा के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता है। यह सच है कि स्थिति की व्यावहारिकता पर अधिक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जब यह न्यायालय इसके बिना 50 वर्षों से अधिक समय तक काम कर सकता है, जिसे कल्पना के किसी भी विस्तार से इतनी छोटी अवधि नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, मुझे यह जोड़ना आवश्यक लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम मुद्दे को फिर से खोलने के परिणामों से चिंतित नहीं हैं, बल्कि हमारी न्याय वितरण प्रणाली की विशेषता, जैसा कि देश में प्रचलित है, न्याय के उचित और प्रभावी प्रशासन का सख्ती से पालन करना है। यदि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के माध्यम से न्याय के ऐसे प्रशासन का कोई प्रभाव पड़ता है या किसी आदेश को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र या जनता के विश्वास के स्नेह के बिना पारित किया जाता है, जैसा कि न्याय वितरण प्रणाली में अखंडता के सिद्धांत के संबंध में तकनीकीता से नहीं होना चाहिए-न्याय के पाठ्यक्रम को उसी तरह से तौलना चाहिए जो पूर्व-ऋण न्याय के सिद्धांत का वास्तविक प्रभाव है। आर वी में सी. जे. लॉर्ड हेवर्ट के कानून के बयान को अक्सर उद्धृत किया गया है। ससेक्स जस्टिस, एक्स पी मैकार्थी, (1924) 1 KB 256 कि यह मौलिक है

सी. ई. कि न्याय केवल नहीं किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से और

निस्संदेह ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस सिद्धांत को रेखांकित किया जाता और उसमें प्रशासित किया जाता। इस संदर्भ में, आर. वी. में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय। बो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन वजीफा मजिस्ट्रेट और अन्या।, पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्ते (नंबर 2) एक अस्थायी निर्णय प्रतीत होता है, जिसमें न्यायपालिका पर जनता का विश्वास न्याय वितरण प्रणाली का बुनियादी मानदंड कहा जाता है-कोई भी

कार्य या कार्रवाई भले ही निष्क्रिय हो, यदि न्यायपालिका की नैतिकता का क्षरण या क्षरण होने की संभावना है, तो मामले पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

भाई कादरी ने कदमों को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है

न्याय की अवधारणा का उल्लंघन होने की स्थिति में लिया गया और उसके लिए कार्यप्रणाली, इस तरह का विस्तार एक अनावश्यक अभ्यास होगा जिससे मैं बचना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अपनी सहमति दर्ज कर ली है।

तथापि, अंत में इस बात को छोड़कर कि उपचारात्मक याचिकाओं को नियमित के बजाय एक दुर्लभता के रूप में माना जाना चाहिए और न्यायालय की सराहना [2002] 2 एस. सी. आर. की तीन बुनियादी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उचित निरीक्षण पर होनी चाहिए।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1046

हमारी न्याय वितरण प्रणाली के अनुसार, आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है या अधिकार क्षेत्र के बिना है या विवादग्रस्त विषय के साथ किसी न्यायाधीश के जुड़ाव या निकटता के कारण जनता का विश्वास हिलने की भी संभावना है। मेरे विचार में, अब समय आ गया है कि प्रक्रियात्मक न्याय प्रणाली को वैचारिक न्याय प्रणाली को रास्ता देना चाहिए और विधि न्यायालय के प्रयासों को इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए।

वे दिन बीत गए जब कानून की कठोर प्रणाली या उसकी व्याख्या के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता था - वर्तमान में कानूनी अदालतों की लचीलापन इसका सबसे बड़ा गुण है और इस तरह न्याय उन्मुख दृष्टिकोण 21 वीं सदी में प्रयास करने और आगे बढ़ने के लिए आज की आवश्यकता है। कोई लागत नहीं।

याचिका

ओं का जवाब दिया।